संस्करण ● नई दिल्ली ● पानीपत (हरियाणा) ● चण्डीगढ़ ● लखनऊ ● भोपाल (मध्य प्रदेश) ● हल्द्वानी नैनीताल ● देहरादून (उत्तराखण्ड) से एक साथ प्रकाशित... www.publicasia.in

पब्लिक की सुनें, पब्लिक की कहें

पब्लिक एशिया

@publicasia1989 @publicasiaofficial @publicasia e-mail: publicasia1989@gmail.com

वर्ष : 15, अंक : 268 पृष्ठ : 04, पानीपत, शुक्रवार 08 नवंबर 2024, मूल्य : 2 रूपये RNI No.- HARHIN/2011/40057

आतंकवाद रोधी राष्ट्रीय योजना और रणनीति लेकर आएगी सरकार : शाह

एजेंसी

नई दिल्ली » केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश में आतंकवाद और आतंकवादी तंत्र से लड़ने के लिए एक मजबूत आतंकवाद रोधी इकोसिस्टम खड़ा करने के लिए जल्द ही आतंकवाद रोधी राष्ट्रीय योजना और रणनीति लेकर आयेगी।

उन्होंने सभी राज्यों से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होने तथा पुलिस बलों को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस करने तथा डाटा के जरिये आतंकवाद का मजबूती से मुकाबला करने का भी आह्वान किया। श्री शाह ने गुरूवार को यहां राष्ट्रीय जांच एजेन्सी (एनआईए) द्वारा आयोजित दो दिन के आतंकवाद रोधी सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि सरकार आतंकवाद से लड़ने के लिए अगले कदम के रूप में जल्द ही आतंकवाद रोधी राष्ट्रीय योजना और रणनीति लेकर आ रही है। उन्होंने कहा , ' टेररिज्म और टेररिज्म सिस्टम से लड़ने के लिए गृह मंत्रालय ने जो प्रोएक्टिव अप्रोच बनाया है उसमें हम एक अगला कदम लेकर आ रहे हैं। कुछ महीनो में नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी लेकर हम आएंगे जिसमें आप सब की भूमिका

स्ट्रेटजी का दस्तावेज बनाने की होगी।'

उन्होंने कहा कि पुलिस राज्यों का विषय है तो लड़ना तो राज्यों को ही पड़ेगा लेकिन केन्द्र इसमें उनकी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार है। राज्यों में पुलिस द्वारा प्रौद्योगिकी के अधिक से अधिक इस्तेमाल तथा प्रशिक्षण पर बल देते हुए उन्होंने कहा , ' जब तक हम हमारी पूरी फोर्स को तकनीक के उपयोग से प्रशिक्षित नहीं करेंगे आतंकवाद के खिलाफ हम नहीं लड़ सकते। अब आतंकवाद का सामना जो हमें करना है वह समझ कर चलिए उसे सीमाहीन और अदृश्य तरीके से आतंकवादी हमले और उनका षड्यंत्र हमारे खिलाफ खड़ा है। हमें टेक्नोलॉजी से हमारे युवा अफसर को लैस करना पड़ेगा। प्रौद्योगिकी को उनकी ट्रेनिंग का एक अहम हिस्सा बनाना होगा। कई सारे राज्यों ने बनाया है। मैं सभी राज्यों को कहना भी चाहता हूं अगर आप को इसमें मदद की जरूरत है तो हैदराबाद की अकादमी भी आपको मदद कर सकती है।'

उन्होंने कहा कि जहां तक आतंकवाद से निपटने का सवाल है राज्यों की अपनी सीमाएं हैं, राज्यों की भौगोलिक सीमाएं भी है, संवैधानिक सीमाएं भी है और आतंकवाद और आतंकवादियों की कोई सीमा नहीं है। वह अंतर राज्य षड्यंत्र करते हैं, अंतरराष्ट्रीय भी षड्यंत्र करते हैं इसलिए इसके खिलाफ हमें केन्द्रीय स्तर पर सटीक तरीके से अपनी रणनीति बनानी है।

श्री शाह ने सभी राज्यों के पुलिस अधिकारियों से तीनों नये आपराधिक कानूनों को पूरी तरह से लागू करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि 26 नवम्बर संविधान दिवस है और पुलिस को लंबे समय से जेलों में बंद ऐसे लोगों को जमानत दिये जाने की दिशा में कार्य करना चाहिए जो इसके हकदार हैं।गृह मंत्री ने इस अवसर पर 11 पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत भी किया और आजादी के बाद से अब तक देश की आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की सुरक्षा बनाए रखने के लिए बलिदान देने वाले 36 हजार 468 पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की।

बंगलादेश में हिन्दुओं की सुरक्षा दे अंतरिम सरकार : भारत

एजेंसी

नई दिल्ली » भारत ने बंगलादेश के चटगांव में हिन्दू अल्पसंख्यकों पर हमले और लूटपाट की निंदा करते हुए वहां की अंतरिम सरकार से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने एवं हिन्दुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यहां नियमित ब्रीफिंग में बंगलादेश की घटनाओं के बारे में पूछे जाने पर कहा कि चटगांव में सोशल मीडिया पर हिन्दू समुदाय को निशाना बना कर भड़काऊ टिप्पणियां किये जाने के बाद वहां बहुत झगड़ा हुआ। हिन्दू समुदाय के लोगों के घरों पर हमला किया गया और लूटपाट की गयी जिसके पीछे उग्रवादी तत्वों का हाथ है। यह अत्यंत निंदनीय है। श्री जायसवाल ने कहा, 'इस प्रकार की बातों से समाज में संतुलन बिगड़ता है और तनाव बढ़ता है। हमारा बंगलादेश की सरकार से आग्रह है कि दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाये और हिन्दुओं को सुरक्षा दी जाये।' बंगलादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की स्थिति को लेकर पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि भारत की दृष्टि में श्रीमती हसीना 'पूर्व प्रधानमंत्री' हैं।

विज्ञापन के बाद भर्ती प्रक्रिया में नही किया जा सकता बदलाव : सुप्रीम कोर्ट

एजेंसी

नई दिल्ली » उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि किसी पद के लिए विज्ञापन जारी होने के बाद भर्ती प्रक्रिया को बीच में नहीं बदला जा सकता। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा, न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की संविधान पीठ ने 'तेज प्रकाश पाठक बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय' मामले में यह फैसला सुनाते हुए कहा कि उम्मीदवारों को आश्चर्य चकित करने के लिए नियमों को नहीं बदला जा सकता।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया के शुरू में अधिसूचित चयन सूची में रखे जाने के लिए पात्रता मानदंड को बीच में नहीं बदला जा सकता, जब तक कि मौजूदा नियम या विज्ञापन (जो मौजूदा नियमों के विपरीत न हो) इसकी अनुमति न दे।

न्यायमूर्ति मिश्रा ने पीठ की ओर से फैसला सुनाते हुए यह भी कहा कि चयन सूची में रखे जाने के बाद उक्त पद के उम्मीदवार को नियुक्ति का अविभाज्य अधिकार प्राप्त नहीं होता, लेकिन सरकार या उसके तंत्र वास्तविक कारणों से रिक्तियों को नही भरने का विकल्प चुन सकते हैं। हालांकि, यदि रिक्तियां मौजूद हैं, तो सरकार या उसके तंत्र चयन सूची में विचाराधीन क्षेत्र

के किसी व्यक्ति को नियुक्ति देने से मनमाने ढंग से इनकार नहीं कर सकते।

इस मामले को 'तेज प्रकाश पाठक और अन्य बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय और अन्य' (2013) के मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेजा गया था, जिसने कि 'मंजूश्री बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य (2008), के मामले में पिछले फैसले पर संदेह जताया था। इस मामले कहा गया था कि चयन मानदंड को बीच में नहीं बदला जा सकता है। संविधान पीठ ने जुलाई में सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

मौसम

दिल्ली/एनसीआर

अधिकतम ता.	न्यूनतम ता.
30.0°C	19.0°C

संक्षिप्त समाचार

धनखड़ ने दी छठ पूजा की शुभकामनायें

एजेंसी

नई दिल्ली » उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देशवासियों को छठ पूजा की शुभकामनायें दी है। श्री धनखड़ ने

गुरुवार को जारी संदेश में कहा कि सूर्य देव की उपासना का यह विशेष पर्व न केवल हमारी सनातन परंपराओं को दर्शाता है, बल्कि प्रकृति के साथ हमारे गहरे रिश्ते का भी प्रतीक है। उन्होंने कहा, ' हमारे देश का पावन त्योहार छठ पूजा आज हम सब के लिए मंगलमय हो। छठी माता की कृपा से हमारा राष्ट्र प्रगति और समृद्धि के पथ पर अग्रसर हो। '

मोदी ने छठ पर्व के संध्या अर्घ्य की शुभकामनाएं दीं

एजेंसी /नई दिल्ली » प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को लोगों को छठ पर्व के संध्या अर्घ्य की शुभकामनाएं प्रेषित की। श्री मोदी ने इस अवसर पर शुभकामना संदेश में कहा, 'छठ के संध्या अर्घ्य के पावन-पुनीत अवसर पर आप सभी को मेरी असीम शुभकामनाएं।' प्रधानमंत्री ने कहा है, 'सादगी, संयम, संकल्प और समर्पण का प्रतीक यह महापर्व हर किसी के जीवन में सुख-समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए। जय छठी मइया।'

ट्रंप प्रशासन के साथ कोई गतिरोध नहीं आएगा : भारत

एजेंसी

नई दिल्ली » भारत ने आज भरोसा जताया कि अमेरिका में निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के साथ व्यापार सीमा शुल्क एवं उत्प्रवासन जैसे मुद्दों पर कोई गतिरोध नहीं आएगा और परस्पर बातचीत से संतोषजनक समाधान निकल आएगा।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यहां नियमित ब्रीफिंग में श्री ट्रंप के शासन काल में भारत-अमेरिका संबंधों में प्रगति और एच-1बी वीजा के बारे में पूछे जाने पर कहा, 'भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक संबंध काफी व्यापक हैं। पिछले साल 2023 में भारत और अमेरिका के बीच करीब 190 अरब डॉलर का व्यापार हुआ, जिसमें सामान और सेवाएं शामिल थीं। अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार है... जहां तक एच-1बी का सवाल है, गतिशीलता और प्रवास साझेदारी हमारे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों का एक हिस्सा है और हमारे कई पेशेवर अमेरिका में काम करते हैं, कई भारतीय छात्र वहां पढ़ते हैं और रक्षा प्रौद्योगिकी में अमेरिका और भारत के बीच बड़ी निवेश साझीदारी है।'

उन्होंने कहा कि हाल में भारत एवं अमेरिका के बीच विश्व व्यापार संगठन

(डब्ल्यूटीओ) के संबंध में सात मुद्दों को सुलझाया गया है। हमारे संबंध और मजबूत हुए हैं।

दोनों देशों के बीच बाकी जो भी मुद्दे हैं, हम इन सभी मुद्दों पर उनके साथ अच्छी बातचीत करना चाहेंगे। उत्प्रवासन के सवाल पर प्रवक्ता ने कहा, 'हम चाहते हैं कि हमारे लोग कानूनी रूप से अमेरिका जाएं। भारत को विश्व भर में कौशल एवं प्रवीणता की राजधानी के रूप में देखा जाता है। हमारा (भारत अमेरिका) गठजोड़ कारोबार, नवान्वेषण एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में है। हम कभी नहीं चाहते हैं कि हमारे लोग अवैध रूप से या बिना पूर्ण दस्तावेज के अमेरिका जायें। इस बारे में हमारी अमेरिकी अधिकारियों से सतत बातचीत हो रही है। हाल ही में अवैध रूप से अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को स्वदेश भेजा गया है। और भी जो लोग अवैध रूप से रह रहे हैं, उनको भी वापस आना चाहिए। अमेरिका में वैध प्रवासन की पर्याप्त संभावनाएं हैं।'

व्यवसाय विरोधी नहीं, कारोबार में एकाधिकारवाद के खिलाफ हूं : राहुल

एजेंसी

नई दिल्ली » कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा है भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उन्हें व्यवसाय विरोधी करार देना का प्रयास कर रही है लेकिन

सच यह है कि वह कारोबार नहीं बल्कि व्यवसाय में एकाधिकारवाद के खिलाफ हैं।

श्री गांधी ने आज वीडियो संदेश में कहा,'भाजपा ने मुझे व्यवसाय विरोधी के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है लेकिन मैं साफ बता देना चाहता हूं कि मैं बिजनेस विरोधी नहीं हूं बल्कि बिजनेस में एकाधिकारवाद के खिलाफ हूं। मैं उस नीति का विरोधी हूं जिसमें एक दो तीन चार पांच लोग ही पूरी तरह से कारोबार पर प्रभावी रहें।' उन्होंने यह भी स्पष्ट किया,'मैं नौकरियों का समर्थक हूं, व्यवसाय का समर्थक हूं, नवप्रवर्तन का समर्थक हूं, प्रतिस्पर्धा का समर्थक हूं लेकिन मैं एकाधिकार विरोधी हूं।हमारी अर्थव्यवस्था तभी फलेगी-फूलेगी जब सभी व्यवसायों के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष स्थान होगा।'

पंजाब के विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा, डॉ. दिलजीत सिंह चीमा, शिअद के महासचिव (पूर्व शिक्षा मंत्री) परगट सिंह, पूर्व शिक्षा मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति पंजाब विश्वविद्यालय में सीनेट चुनाव नहीं होने के संबंध में मीडिया को संबोधित करते हुए और चंडीगढ़ में वीसी कार्यालय के बाहर पंजाब विश्वविद्यालय के छात्रों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए।

ओ आर ओ पी पूर्व सैनिकों के साहस और बलिदान को श्रद्धांजलि : मोदी

एजेंसी

नई दिल्ली » प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) योजना को राष्ट्र की सेवा में जीवन समर्पित करने वाले पूर्व सैनिकों के साहस और बलिदान के लिए श्रद्धांजलि करार देते हुए कहा कि सरकार सशस्त्र बलों को मजबूत बनाने और उनके कल्याण के लिए हर संभव प्रयास करती रहेगी।

श्री मोदी ने ओ आर ओ पी लागू किये जाने के दस वर्ष पूरे होने के मौके पर गुरूवार को यह बात कही।प्रधानमंत्री

ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा,' यह हमारे पूर्व सैनिकों के साहस और बलिदान के लिए एक श्रद्धांजलि है, जो हमारे राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। उन्होंने कहा कि ओआरओपी को लागू करने का निर्णय लंबे समय से चली आ रही इस मांग को पूरा करने और हमारे नायकों के प्रति हमारे देश की कृतज्ञता की पुष्टि करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। 'श्री मोदी ने देश को आश्वस्त किया कि सरकार सशस्त्र बलों को मजबूत करने और सैनिकों के कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा हर संभव प्रयास करेगी। एक अन्य पोस्ट में उन्होंने कहा , ' आप सभी को खुशी होगी कि एक दशक में, लाखों पेंशनभोगी और पेंशनभोगी परिवार इस ऐतिहासिक पहल से लाभान्वित हुए हैं। संख्या से परे, ओआरओपी हमारे सशस्त्र बलों की भलाई के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है।

छठ महापर्व हमें प्रकृति से प्रेम, जल व वायु को स्वच्छ रखने और सामाजिक समरसता का देता है संदेश : नायब सैनी

मुख्यमंत्री ने महा छठ पर्व महोत्सव में करनाल में बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत

पब्लिक एशिया ब्यूरो

चंडीगढ़ » हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीरवार को महा छठ पर्व महोत्सव के अवसर पर करनाल में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले पश्चिमी यमुना नहर के किनारे पर स्थापित भगवान सूर्य देव मंदिर में पूजा-अर्चना की तथा आर्शीवाद लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने समिति की ओर से रखी गई सभी मांगों को स्वीकार किया और अपने ऐच्छिक कोष से 21 लाख रुपये की राशि अनुदान के रूप में देने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने उपस्थित श्रद्धालुओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि यह मेरा परम सौभाग्य है कि सूर्य पुत्र महावीर-दानवीर कर्ण की नगरी करनाल में छठ पर्व की पूजा में शामिल होने का अवसर मिला है। मैं सभी माताओ-बहनों को छठ महापर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही कामना करता हूं कि छठ मैया सदैव आपकी झोली खुशियों से भरकर रखे। उन्होंने कहा कि मूल रूप से पूर्वांचल में मनाया जाने वाला यह पर्व अब विभिन्न प्रदेशों की सीमाएं लांघकर देशभर में मनाया जाने लगा है। उन्होंने

कहा कि छठ महापर्व हमें प्रकृति से प्रेम, जल व वायु को स्वच्छ रखने और सामाजिक समरसता का संदेश देता है। सूर्य की उपासना की परंपरा इस बात का प्रमाण है कि हमारी संस्कृति व आस्था का प्रकृति से गहरा जुड़ाव है। छठ पूजा के जरिए हमारे जीवन में सूर्य के प्रकाश के महत्व को बताया गया है। चढ़ते सूरज की पूजा हर कोई करता है, लेकिन आप सूरज के हर रूप की पूजा करते हैं। इसमें ढलते सूरज की पूजा करना भी अद्भुत है। इससे यह संदेश जाता है कि हमें जीवन के उतार-चढ़ाव में समान भाव रखना चाहिए। छठ पूजा को सूर्य उपासना का सबसे पवित्र पर्व माना गया है। ऊर्जा और जीवन शक्ति के देवता सूर्य नारायण की पूजा इस पर्व के दौरान मनोकामना पूर्ति, समृद्धि और प्रगति प्रदान करने के लिए की जाती है। इस पर्व के दौरान सभी श्रद्धालु जल में खड़े होकर भगवान सूर्यनारायण को जल अर्पित करते हैं। इससे हमारे मन में यह भाव भी दृढ़ हो जाता है, जिस तीर्थ के जल में हम पूजा करते हैं, उसे साफ-सुथरा रखना हमारा कर्तव्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवरात्र की तरह यह पर्व भी साल में दो बार मनाया जाता है. पहली बार चैत्र मास में और दूसरी बार कार्तिक मास में आता है। छठ पूजा का सम्बन्ध हरियाणा से भी है। एक मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्यदेव की पूजा शुरू की थी। आज भी यहां सूर्य पूजा का विशेष प्रभाव दिखता है। यह पर्व आपसी प्रेम और समानता का संदेश भी देता है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ही मार्गदर्शन में 'श्रमेव जयते' में विश्वास करते हुए पिछले 10 वर्षों में गरीब जनता की सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं। जहां श्रमिकों की कार्यस्थल पर सुरक्षा को मजबूत बनाया है, वहीं उनका दुर्घटना बीमा भी किया जाता है और उनके सामाजिक सरोकारों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। श्रमिक परिवारों को कन्यादान स्कीम के तहत तीन बेटियों की शादी तक हर शादी में 51 हजार रुपये का कन्यादान तथा 50 हजार रुपये शादी का प्रबंध करने के लिए दिये जाते हैं। इसी प्रकार, बेटे व स्वयं की शादी पर भी 21 हजार रुपये की शगुन राशि दी जाती है।उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री महिला निर्माण श्रमिक सम्मान योजना के तहत सभी पंजीकृत श्रमिक बहनों को कपड़ों व उनकी व्यक्तिगत जरूरत के लिए 5100 रुपये की सालाना वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अलावा महिला श्रमिकों को सिलाई मशीन खरीदने के लिए 4500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

महिला श्रमिकों को प्रसूति के उपरांत 36 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। श्रमिक की कार्य-स्थल पर दुर्घटना होने पर श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा तुरन्त 3 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। बोर्ड द्वारा श्रमिकों की दिव्यांगता पेंशन 3,000 रुपये कर दी गई है और 60 वर्ष की आयु उपरान्त 1000 रुपये की राशि अतिरिक्त दी जाती है। मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक की काम के दौरान दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर श्रमिक के परिवार को 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के कल्याण के लिए हरियाणा असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा बोर्ड गठित किया गया है। न्यूनतम वेतन प्रणाली की विसंगतियों को भी दूर किया है।

सूर्य उपासना और लोक आस्था का पर्व है छठ पूजा

चंडीगढ़ » भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं हिमाचल के सह प्रभारी संजय टंडन ने कहा कि छठ पूजा का महापर्व सूर्य उपासना और लोक आस्था का पर्व है।

यह पर्व सभी के जीवन में नई ऊर्जा और शक्ति लेकर आता है। सादगी, संयम, दृढ़ संकल्प और समर्पण का प्रतीक यह महान पर्व सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए। संजय टंडन ने छठ पूजा के अवसर पर चंडीगढ़वासियों को बधाई दी। उन्होंने सेक्टर-42 लेक पर आयोजित छठ पूजा समारोह में शिरकत की और मंत्रोच्चारण के बीच सूर्य देव को अर्घ्य दिया। इस दौरान पूर्वांचल वेलफेयर महाससभा चंडीगढ़, पूर्वांचल युवा सेवा समिति और वेलफेयर ऑफ किरायेदार खजहेड़ी चंडीगढ़ ने संजय टंडन को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। छठ के संध्या अर्घ्य के पावन- अवसर पर संजय टंडन ने शुभकामनाएं दी।

संपादकीय

क्योंकि, 'कमला' तुम केवल 'कमला' हो

कमला हैरिस अमेरिका की राष्ट्रपति नहीं बन पायी। उनकी छलांग उप राष्ट्रपति तक हिसिमित कर रह गयी। कमला हैरिस को भी शायद ये पता होगा की जिस देश में वे रहतीं हैं वो देश पिछले 225 साल से पुरुषों के हाथ में है। महिला-पुरुष के बीच तमाम बराबरी की वकालत करने वाले अमेरिका का पुरुष प्रधान समाज देश के सर्वोच्च पद पर किसी महिला को बर्दाश्त करने की स्थिति में अब तक आया ही नहीं है। इस मामले में अमेरिका भारत से भी मीलों पीछे है। मुझे कमला हैरिस की पराजय से कोई हैरानी नहीं हुई। मै ये भी नहीं कह सकता की चुनाव में उनके साथ वैसी चीटिंग हुई होगी जैसी भारत और दूसरे देशों में होने की गुंजाइशें होती है। हकीकत तो ये है की कमला या किसी दूसरी महिला को अमेरिका कभी राष्ट्रपति के रूप में स्वीकार कर ही नहीं सकता। कहते हैं की भारत यदि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है। अमेरिका की जनता को पहले भी हाथी पसंद था, और इस बार भी उसे ही चुना गया हालाँकि बीच में गधा भी अमेरिका की जनता पसंद करती रही है। मै अमेरिका के दो प्रमुख दलों के चुनाव चिन्हों की बात कर रहा हूँ। क्योंकि अमेरिका में कोई नेता गधा नहीं हो सकता।

हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के दोस्त डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका के 130 साल के इतिहास में ऐसे पहले राष्ट्रपति हैं जो कि पिछली बार चुनाव में पराजय का स्वाद चख चुके हैं। यानि वे अमेरीका के इतिहास पुरुष तो बन ही गए है। अब पूरे चार साल दुनिया में ट्रम्प साहब का ही डंका बजेगा।ट्रम्प के पास भी वैसे ही अंधभक्त हैं जैसे की भारत में मोदी जी के पास है। आपको याद होगा की ट्रम्प साहब के भक्त गुस्से में उस व्हाइट हाउस पर चढ़ गए थे ,जिस पर वे लम्बी प्रतीक्षा के बाद विधिवत पहुँच रहे हैं। भारत अब अमेरिका के साथ किस तरह से जुगलबंदी बनाएगा येकहना कठिन भी है और जल्दबाजी भी। अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन की निष्क्रियता और अस्पष्ट विदेश नीति की वजह से हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी अपना डंका बजानेमें लगे थे। वे अपने घर में लगी आग की अनदेखी कर रूस और यूक्रेन के बीच की जंग को समाप्त करने के लिए प्रयत्नशील थे। उन्होंने चीन और पाकिस्तान के साथ भी बिगड़े रिश्ते सुधारने की पहल की। ट्रैम्प को न शांतिदूत बनाना है औरन विश्व गुरु। वे विश्व दादा जरूर बनना चाहेंगे। वे विश्व के नए दादा बन भी सकते हैं।

डोनाल्ड ट्रम्प के आने से अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के जीवन पर क्या फर्क पडेगा,इसकी आहट वहां रहने वालों को पहले ही मिल चुकी है। ट्रंप का कार्यकाल भारत के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। ट्रंप के नेतृत्व में अगर नया अमेरिकी प्रशासन 'अमेरिका फर्स्ट' एजेंडा को आगे बढ़ाने का फैसला करता है, तो भारतीय एक्सपोर्टर्स को ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और फार्मा के लिए ज्यादा कस्टम ड्यूटी का सामना करना पड़ सकता है। ट्रम्प की वीजा नीति भारत हितैषी होगी या विरोधी ,कहना कठिन है। अमेरिका में जिस तरह से बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी है उसे देखते हुए लगता है की ट्रम्प साहब भारतीयों का ख्याल रखने से पहले अपने नागरिकों का ख्याल रखेंगे।

विशेषज्ञों की मानें तो कि ट्रंप एच-1बी वीजा नियमों को भी सख्त कर सकते हैं, जिससे भारतीय आईटी कंपनियों की लागत और वृद्धि पर असर पड़ेगा। भारत में 80 प्रतिशत से ज्यादा आईटी एक्सपोर्ट इनकम अमेरिका से आती है, जिससे वीजा पॉलिसी में बदलाव के प्रति भारत संवेदनशील हो जाता है। अमेरिका, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। अमेरिका से भारत का सालाना कारोबार 190 अरब डॉलर से ज्यादा है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के संस्थापक अजय श्रीवास्तव को लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप चीन के बाद अब भारत और अन्य देशों पर भी शुल्क लगा सकते हैं। ट्रंप ने पहले भारत को 'बड़ा शुल्क दुरुपयोगकर्ता' कहा था और अक्टूबर, 2020 में भारत को 'टैरिफ किंग' करार दिया था। डोनाल्ड ट्रम्प के सामने ठीक वैसी ही समस्याएं हैं जैसी की भारत में माननीय मोदी जी के सामने है। लेकिन मोदी जी और ट्रम्प में एक और समानता ये भी है कि दोनों कहते हैं की नामुमकिन कुछ भी नहीं है। दोनों नेताओं का आत्म- विश्वास बेमिसाल है। दोनों की बेमिसाल जोड़ी आने वाले दिनों में देश-दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था को किस सीमा तक प्रभावित करेंगे ? ये जानने के लिए महीने-दो महीना इन्तजार करना होगा। ट्रम्प से हटाकर बात करें तो अमेरिका में कोई महिला कब राष्ट्रपति बनेगी इसका इन्तजार भी दुनिया को है। इस मामले में भारत अमेरिका से बहुत आगे हैं। भारत क्या दुनिया के बहुत से देशों के रष्ट्र प्रमुख महिलाओं को शिरोधार्य कर चुके हैं। विश्व कि महिला राष्ट्राध्यक्षों कि सूची में अमेरिका का नाम अब तक जुड़ा ही नहीं है। यानि इस मामले में अमेरिका बदनसीब है।

विश्व के ज्यादातर देशों में महिलाओं के हाथ में देश के शीर्ष राजनीतिक पदों की कमान नहीं रही है। यहां तक कि विश्व के लगभग 79 देशों के राजनीतिक समीकरण में आज तक एक भी महिला को जगह नहीं मिली है।भारत इस मामले में सबसे आगे रहा है। भारत में श्रीमती इंदिरा गांधी और प्रतिभा पाटिल का नाम सबसे ऊपर आता है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में दो भागों में 16 सालों तक प्रधानमंत्री पद की कमान संभाली। पहले भाग में 1966 से लेकर 1977 तक और फिर दूसरे भाग में 1980 से लेकर 198 4 इंदिरा ने भारत के प्रधानमंत्री पद का दायित्व संभाला। इसके बाद नाम आता है प्रतिभा पाटिल का, जिन्होंने 2007 से लेकर 2012 तक भारत का राष्ट्रपति होने का गौरव हासिल किया।श्रीमती द्रोपदी मुर्मू इस समय भारत कि राष्ट्रपति हैं ही। अभी तो अमेरिका की महिलाओं की स्थितियों पर भारत के राष्ट्र कवि मैथली शरण गुप्ता की वो पंक्तियाँ याद आतीं हैं ,जिनमें उन्होंने लिखा था की -

अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी,
आँचल में है दूध और आँखों में पानी
वे यदि आज होते तो लिखते की -
कमला हैरिस हाय ! तुम्हारी यही कहानी ।
सीने में है क्षोभ और आँखों में पानी।।

▪ *राकेश अचल*

विशेष दर्जे की बहाली का प्रस्ताव अंधेरों की आहट

ललित गर्ग

घाटी के राजनीतिक दलों को वहां के अवाम के हित में सोचना चाहिए। क्योंकि अनुच्छेद 370 के खत्म होने से राज्य का कोई नुकसान हुआ, ऐसा नहीं दिखता। इसलिए जम्मू-कश्मीर को अब ऐसी राजनीति की जरूरत है, जो विशेष दर्जे से इतर तरक्की का नया खाका खींचे। अनुच्छेद 370 का खत्म होना इसलिये ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि वहां के लोगों ने साम्प्रदायिकता, राष्ट्रीय-विखण्डन, आतंकवाद तथा घोटालों के जंगल में एक लम्बा सफर तय करने के बाद अमन-शांति, सौहार्द एवं विकास को साकार होते हुए देखा है। उनकी मानसिकता घायल थी तथा जिस विश्वास के धरातल पर उसकी सोच ठहरी हुई थी, वह भी हिली है।

नेशनल कॉन्फ्रेंस एवं उमर अब्दुला सरकार ने सदन में अपने बहुमत का लाभ उठाते हुए बुधवार को बिना अनुच्छेद 370 की पुर्नबहाली शब्द का इस्तेमाल कर, विशेष दर्जे की बहाली का प्रस्ताव तीखी झड़पों, हाथापाई, लात-घूंसे एवं शोरशराबे के बीच ध्वनिमत से पारित करा, साबित कर दिया है, वह पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इस होड़ में पीछे रहने के मूड में नही है। ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर में अलगाववाद और तुष्टिकरण की राजनीति फिर से परवान चढ़ने लगी है, आम कश्मीरी अवाम को गुमराह कर उसे बर्बादी की तरफ धकेलने की कुचेष्टाएं प्रारंभ हो गयी है। इस पारित प्रस्ताव में केंद्र सरकार से कहा गया है कि वह विशेष दर्जा वापस देने के लिए राज्य के प्रतिनिधियों से बातचीत करे। बुधवार को नवगठित राज्य विधानसभा में जब यह प्रस्ताव उप-मुख्यमंत्री सुरिंदर सिंह चौधरी ने पेश किया, तभी यह स्पष्ट हो गया था कि चौधरी का चयन ही इसलिए किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश न कर सके। लेकिन भाजपा ने एक विधान एक निशान और राष्ट्रवाद के प्रति अपनी संकल्पबद्धता को दोहराते हुए इस प्रस्ताव का विरोध कर बताया कि वह प्रत्यक्ष तो क्या परोक्ष तौर पर भी किसी को घड़ी की सुइयां पीछे मोढ़ने की अनुमति नहीं देगी। जब तक केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की नरेन्द्र मोदी सरकार है, कोई भी अनुच्छेद 370 और 35ए को वापस नहीं ला सकता। अनुच्छेद 370 एक मरा हुआ सांप है, जिसे वह एक गले से दूसरे गले में डाल, जहर, आतंक एवं हिंसा फैलाने के षडयंत्र को सफल नहीं होने देगी। कश्मीर के नेताओं को समझना ही होगा कि पूरे भारत में अनुच्छेद 370 को लेकर जैसा जनमानस है, उसे देखते हुए अनुच्छेद 370 की वापसी असंभव है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर की धरती पर अनेक सकारात्मक स्थितियां उद्घाटित हुई है, विशेषतः लोकतंत्र को जीवंतता मिली है, वहां की अवाम ने चुनावों में बढ़-चढ़कर भाग लिया, शांति एवं विकास से इस प्रांत में एक नई इबारत लिखी जाने लगी है। जम्मू-कश्मीर हमारे देश का वो गहना है जिसे जब तक सम्पूर्ण भारत के साथ जोड़ा नहीं जाता, वहां शांति, आतंकमुक्ति एवं विकास की गंगा प्रवहमान नहीं होती, अधूरापन-सा नजर आता रहा है। इसलिए इसे शेष भारत के साथ हर दृष्टि से जोड़ा जाना महत्वपूर्ण है और यह कार्य मोदी एवं उनकी सरकार ने करके एक नये सूरज को उदित किया है, अब उस सूरज को अस्त नहीं होने दिया जायेगा। बड़ी जद्दोजहद से वहां एक नया दौर शुरू हुआ है, अब इस सुनहरे एवं उजले दौर को स्वार्थी एवं सत्ता की अलगाववादी एवं विघटनकारी राजनीति की भेंट नहीं चढ़ने देना चाहिए।

भारत की महानता उसकी विविधता में है। साम्प्रदायिकता एवं दलगत राजनीति का खेल, उसकी विविधता में एकता की पीठ में छुरा भोंकता रहा है, घाटी उसकी प्रतीक बनकर लहूलुहान रही है। जब हम नये भारत-सशक्त भारत बनने की

ओर अग्रसर हैं, विश्व के बहुत बड़े आर्थिक बाजार बनने जा रहे हैं, विश्व की एक शक्ति बनने की भूमिका तैयार करने जा रहे हैं, तब हमारे मस्तक के ताज जम्मू-कश्मीर को जाति, धर्म व स्वार्थी राजनीति से बाहर रखना सबसे बड़ी जरूरत है। इसी दिशा में घाटी को अग्रसर करने में मोदी सरकार के प्रयत्न सराहनीय एवं स्वागतयोग्य रहे हैं। घाटी की कमजोर राजनीति एवं साम्प्रदायिक आग्रहों का फायदा पडोसी उठा रहे हैं, जिनके खुद के पांव जमीन पर नहीं वे आंख दिखाते रहे हैं। अब ऐसा न होना, केन्द्र की कठोरता एवं सशक्तीकरण का द्योतक हैं। कश्मीर के तथाकथित राजनीतिक कर्णधारों ! अलगाववाद और तुष्टिकरण की राजनीति छोड़ो। अगर तेवर ही दिखाने हैं तो देश के दुश्मनों को दिखाओ, पडौसी देश के मनसूबों को निस्तेज करों। अतीत की राजनीतिक भूलों को सुधारना और भविष्य के निर्माण में सावधानी से आगे कदमों को बढ़ाना, जम्मू-कश्मीर की चुनी हुई सरकार का संकल्प होना चाहिए।

विशेष राज्य का दर्जा पाने के मसले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जहां खड़ी है, पीडीपी उससे दो कदम आगे रहना चाहती है। ऐसे करके नेशनल कान्फ्रेंस और पीडीपी सरीखे दल यहां अलगाववाद और एक वर्ग विशेष की तुष्टिकरण की राजनीति को जारी रखना चाहते हैं, वह यहां फिर से अलगाववाद को पैदा करना चाहते हैं, आम कश्मीरी अवाम को गुमराह कर उसे बर्बादी की तरफ धकेलना चाहते हैं, तभी अनुच्छेद 370 की बहाली का प्रस्ताव लाये हैं। जबकि अनुच्छेद 370 के हटने से घाटी में एक उजाला अवतरित हुआ है, अब फिर से घाटी को अंधेरों से नहीं घिरने देना चाहिए। भले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू-कश्मीर का चुनाव ही इसी घोषणा के साथ लड़ा और जीता है कि वह भारतीय संविधान में राज्य को उसका विशेष दर्जा वापस दिलाएगी। इसीलिये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सत्ता में आते ही पहला काम यही किया और विधानसभा ने राज्य को विशेष दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव पारित कर दिया।

नेशनल कान्फ्रेंस को लगता है कि विशेष दर्जे के मुद्दे से कुछ लोगों के तार भावनात्मक रूप से जुड़े हैं, इसलिए ज्यादा अतिवादी रूख अपनाकर इसका कुछ राजनीतिक फायदा उठाया जा सकता है। दोनों ही प्रमुख दल इस मुद्दे का राजनीतिक लाभ उठाने की होड़ लगाते हुए दिख रहे हैं। तभी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की टिप्पणी थी कि यह पीडीपी का केवल प्रचार स्टंट है और उसके विधायक सिर्फ कैमरे के आगे आने के लिए यह सब कर रहे हैं। मगर उमर अब्दुल्ला जो बात पीडीपी के लिए कह रहे हैं, वही शायद उनके लिए भी कही जा सकती है, वरना वह भी यह जानते हैं कि 5 अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के जिस अनुच्छेद 370 को खत्म किया गया था, उसकी वापसी अब इतनी आसान नहीं है। वैसे भी, इतना तो उन्हें पता ही होगा कि सिर्फ विधानसभा में प्रस्ताव पारित हो जाने भर से अनुच्छेद 370 वापस आने वाला नहीं है। फिर इस समय केंद्र में भाजपा सरकार है, जो किसी भी तरह से इस पर विचार करने के मूड में नहीं है। उसकी नजर में यह एक कागज का टूकड़ा है, जो बिना विचार के रद्दी की टोकड़ी में ही जाने वाला है।

अनुच्छेद 370 को लेकर कश्मीर की जनता और राजनेताओं, दोनों को समझना ही होगा कि 70 साल तक विशेष दर्जा होने के बावजूद इससे राज्य का कोई बहुत भला नहीं हुआ। देश की मूल धारा से कटकर यह प्रांत अंधेरों से घिरा रहा है। हिंसा एवं आतंकवाद की त्रासदी को झेलते हुए विकास एवं शांति की बाट जोहता रहा है। अब विशेष दर्जा हटाने का राज्य को बहुत लाभ मिला है, वहां विकास एवं जनकल्याण के काम तेजी से हो रहे हैं, न केवल विकास योजनाएं आकार ले रही है, बल्कि वहां शांति एवं सौहार्द का वातावरण बना है, आतंकवादी घटनाओं पर भी नियंत्रण किया जा सका है। मोदी की सरकार ने जम्मू-कश्मीर के विकास को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया है। देश के साथ दुनिया को यह संदेश दिया गया कि कश्मीर में किसी का हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं, कश्मीर भारत का ताज है और हमेशा रहेगा।

घाटी के राजनीतिक दलों को वहां के अवाम के हित में सोचना चाहिए। क्योंकि अनुच्छेद 370 के खत्म होने से राज्य का कोई नुकसान हुआ, ऐसा नहीं दिखता। इसलिए जम्मू-कश्मीर को अब ऐसी राजनीति की जरूरत है, जो विशेष दर्जे से इतर तरक्की का नया खाका खींचे। अनुच्छेद 370 का खत्म होना इसलिये ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि वहां के लोगों ने साम्प्रदायिकता, राष्ट्रीय-विखण्डन, आतंकवाद तथा घोटालों के जंगल में एक लम्बा सफर तय करने के बाद अमन-शांति, सौहार्द एवं विकास को साकार होते हुए देखा है। उनकी मानसिकता घायल थी तथा जिस विश्वास के धरातल पर उसकी सोच ठहरी हुई थी, वह भी हिली है। जम्मू-कश्मीर में शांति और सौहार्द के साथ लोकतंत्र और विकास की नई इबारत लिखी गयी है। जम्मू-कश्मीर को अशांत और संवेदनशील क्षेत्र बनाए रखने की कोशिश में लगे तत्वों एवं राजनीतिक दलों से सावधान रहने की जरूरत है, भले ही वे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी या अन्य पाकिस्तान परस्ती राजनीतिक दल।

सोशल मीडिया बनाम पारंपरिक मीडिया; वे कैसे भिन्न हैं ?

एक व्यक्ति अपने दाहिने हाथ में स्मार्टफोन और गले में हेडसेट लटकाए हुए थोड़ा मुस्कुराते हुए आगे की ओर देखता है। मीडिया एक व्यापक उद्योग है जिसमें रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट प्लेटफ़ॉर्म जैसे किसी भी प्रकार का जन संचार शामिल है। सोशल मीडिया और पारंपरिक मीडिया मीडिया क्षेत्र के दो प्राथमिक क्षेत्र हैं, और दोनों विभिन्न दर्शकों तक महत्वपूर्ण जानकारी या अंतर्दृष्टि पहुंचाने के लिए उपयोगी हो सकते हैं। यदि आप मीडिया क्षेत्र में करियर में रुचि रखते हैं या आप विशिष्ट दर्शकों के साथ बातचीत करने के लिए मीडिया का उपयोग करना चाहते हैं, तो इन दो

विजय गर्ग

मीडिया प्रकारों के बारे में अधिक जानने से आपको बेहतर ढंग से यह निर्धारित करने में मदद मिल सकती है कि आपके लिए कौन सा सही हो सकता है। इस लेख में, हम बताते हैं कि सामाजिक और पारंपरिक मीडिया क्या हैं, दो मीडिया प्रकारों के बीच मुख्य अंतरों को सूचीबद्ध करें और प्रत्येक क्षेत्र के भीतर प्राथमिक नौकरियों की एक सूची प्रदान करें। सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया वेबसाइटें, इंटरनेट प्लेटफ़ॉर्म और अन्य प्रौद्योगिकियाँ हैं जो व्यवसायों और व्यक्तियों को ऑनलाइन बातचीत करने की अनुमति देती हैं। विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म हैं जिनमें विभिन्न वेबसाइटें, मैसेजिंग प्लेटफ़ॉर्म और एप्लिकेशन शामिल हैं, और प्रत्येक प्लेटफ़ॉर्म में अलग-अलग विशेषताएं और क्षमताएं हो सकती हैं। कंपनियां अपने उत्पादों या सेवाओं का विज्ञापन करने, ग्राहकों के सवालों का जवाब देने या किसी नए ब्रांड या विचार को प्रसारित करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग कर सकती हैं। पारंपरिक मीडिया क्या है? पारंपरिक मीडिया जनसंचार का एक रूप है जिसमें विशिष्ट दर्शकों के साथ विचार या विज्ञापन साझा करना शामिल है।

पारंपरिक मीडिया में समाचार पत्र, टेलीविजन कार्यक्रम, पत्रिकाएं और रेडियो शो शामिल हो सकते हैं। इसमें इन उपकरणों के डिजिटल संस्करण भी शामिल हो सकते हैं, जैसे कोई ऑनलाइन पत्रिका या ब्लॉग। इंटरनेट से पहले, पारंपरिक मीडिया अक्सर संगठनों द्वारा संभावित ग्राहकों को विज्ञापन देने का प्राथमिक तरीका था। सोशल मीडिया बनाम पारंपरिक मीडिया चाहे आप मीडिया में करियर बनाने पर विचार कर रहे हों या बस किसी व्यवसाय या उत्पाद के विपणन के तरीके तलाश रहे हों, सामाजिक और पारंपरिक मीडिया के बीच अंतर के बारे में सीखने से आपको बेहतर ढंग से यह निर्धारित करने में मदद मिल सकती है कि आपके इच्छित दर्शकों के लिए कौन सा अधिक प्रभावी हो सकता है। इन दोनों प्रकार के मीडिया के बीच कुछ प्रमुख अंतर यहां दिए गए हैं» श्रोता विशिष्ट दर्शकों से जुड़ने के लिए सामाजिक और पारंपरिक दोनों मीडिया उपयोगी उपकरण हो सकते हैं। पारंपरिक मीडिया आमतौर पर व्यवसायों को व्यापक दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, कोई कंपनी राष्ट्रीय टेलीविजन नेटवर्क पर सुबह की खबरों के दौरान अपने उत्पाद का विज्ञापन करने के लिए भुगतान कर सकती है। इससे उस कंपनी को व्यापक दर्शकों को आकर्षित करने की अनुमति मिलती है, क्योंकि बहुत से लोग काम पर निकलने से पहले सुबह समाचार देखना पसंद करते हैं। सोशल मीडिया आम तौर पर छोटे, अधिक विशिष्ट दर्शकों के लिए उपयोगी है। सोशल मीडिया विशेषज्ञ किसी कंपनी के अनुयायियों को लक्षित करने के लिए पोस्ट बना सकते हैं या वे एक निश्चित समूह का ध्यान बनाए रखने के लिए अधिक वैयक्तिकृत विज्ञापन विकसित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक कपड़ा कंपनी जो युवा महिलाओं के लिए कपड़े बनाती है, अपने चैनलों पर एक नए डिज़ाइन के बारे में पोस्ट कर सकती है, जिससे उसके सोशल मीडिया अनुयायियों को पोस्ट को अधिक आसानी से ढूंढने और साझा करने की सुविधा मिलती है। कंपनी की मार्केटिंग टीम पोस्ट को अधिक विशिष्ट आयु समूहों को लक्षित करने और अनुकूलित करने के लिए सोशल मीडिया एल्गोरिदम का उपयोग कर सकती है।

वार्ता सामाजिक और पारंपरिक मीडिया दोनों विभिन्न प्रकार के संचार या संवाद प्रदान करते हैं। पारंपरिक मीडिया अक्सर एक तरफ़ा संचार उपकरण होता है, जिसका अर्थ है कि इसका मुख्य उद्देश्य दर्शकों को सूचित करना या राजी करना है। उदाहरण के लिए, कोई व्यवसाय किसी स्थानीय में विज्ञापन पोस्ट कर सकता हैकिसी संदेश को दर्शकों के साथ शीघ्रता से साझा करने के लिए समाचार पत्र या दिन के समय टेलीविजन पर अपना विज्ञापन प्रसारित करता है। सोशल मीडिया इस मायने में भिन्न है कि यह कंपनियों को अपने इच्छित दर्शकों के साथ दो-तरफ़ा संवाद को बढ़ावा देने और उनके साथ निरंतर बातचीत बनाए रखने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, कोई कंपनी अपने सोशल मीडिया चैनलों पर अपनी नई सेवा का विज्ञापन करते हुए एक तस्वीर पोस्ट कर सकती है। संभावित ग्राहक पोस्ट पर सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया देकर और उसे पसंद करके या अपने अनुयायियों के साथ साझा करके उससे बातचीत कर सकते हैं। इससे कंपनी को अपनी ब्रांड जागरूकता बढ़ाने, ग्राहकों से तुरंत प्रतिक्रिया प्राप्त करने और उनके साथ अधिक आसानी से जुड़ने की अनुमति मिल सकती है। लागत मार्केटिंग के लिए मीडिया की लागत प्रारूप के आधार पर भिन्न हो सकती है। सोशल मीडिया की लागत आमतौर पर पारंपरिक मीडिया की तुलना में कम होती है लेकिन व्यापक दर्शकों को आकर्षित करने के लिए अधिक व्यक्तिगत भुगतान की आवश्यकता हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई मार्केटिंग टीम किसी नए उत्पाद के लिए विज्ञापन पोस्ट करना चाहती है, तो वह मुफ्त में या थोड़ी सी लागत पर एक सोशल मीडिया घोषणा बना सकती है। कोई कंपनी अपने सोशल मीडिया पर जितने अधिक भुगतान वाले विज्ञापन पोस्ट करेगी, वह उतनी ही आसानी से अपने लक्षित दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम हो सकती है।

पारंपरिक मीडिया में अक्सर मीडिया संगठन या कंपनी के आधार पर दरें निर्धारित होती हैं। उदाहरण के लिए, एक कंपनी जो किसी पत्रिका में विज्ञापन पोस्ट करना चाहती है, वह पत्रिका कंपनी को एक विशिष्ट शुल्क का भुगतान कर सकती है। टीवी और रेडियो विज्ञापनों की लागत अक्सर दिन के विशिष्ट समय या दर्शकों की संख्या पर निर्भर करती है। ऐसे शो जिन्हें अधिक दर्शक मिलते हैं या दिन का वह समय जब अधिक लोग कार्यक्रम देख रहे होते हैं, उच्च विज्ञापन लागत से संबंधित हो सकते हैं। समय इन दो मीडिया प्रारूपों के लिए समयरेखा या उत्पादन कार्यक्रम भी भिन्न हो सकते हैं। पारंपरिक मीडिया को आमतौर पर बनाने में अधिक समय लगता है और इसका एक विस्तृत शेड्यूल होता है जो विज्ञापन के विशिष्ट रूप पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, किसी पत्रिका में विज्ञापन देने में रुचि रखने वाली मार्केटिंग टीमों के लिए संभवतः उस पत्रिका के प्रकाशन कार्यक्रम के आधार पर अपने विज्ञापन विकसित करना आवश्यक होगा। इसका अर्थ मासिक विज्ञापन विकसित करना हो सकता है यदि पत्रिका प्रत्येक माह की शुरुआत में नई सामग्री प्रकाशित करती है। सोशल मीडिया में अक्सर अधिक लचीली समयरेखा होती है। कंपनियाँ जानकारी पोस्ट कर सकती हैं और ग्राहकों के साथ शीघ्रता और बार-बार संवाद कर सकती हैं। वे कितने विज्ञापन बनाते हैं और उन्हें पोस्ट करने की आवृत्ति अक्सर उनका निर्णय होता है।

अब भ्रष्टाचार को आतंकवाद का पर्याय मानना अत्यंत ज़रूरी

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं

भारतीय कानूनों में आतंकवाद व भ्रष्टाचार को एक ही परिभाषा के दायरे में लाना समय की मांग। आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 7-8 नवंबर 2024 सराहनीय परंतु अब भ्रष्टाचार को आतंकवाद का पर्याय मानना अत्यंत जरूरी।शासकीय व प्रशासकीय तंत्र में संतरी से मंत्री तक चपरासी से उच्च अफसर तक अगर त्रैमासकीय भ्रष्टाचार विरोधी सम्मेलन करें तो जीरो टॉलरेंस की गारंटी है।

वैश्विक स्तरपर आतंकवाद व भ्रष्टाचार दुनियाँ के हर देश को दीमक की तरह चाटकर बर्बादी के आलम तक पहुंचा रहे हैं,इसलिए हर देश इस महामारी से ग्रस्त है परंतु मेरा मानना है कि यह बात हर किसी के मन में होगी कि बिना किसी उच्चस्तरीय सहयोगसे यह दोनों बीमारियां पनपेगी नहीं, जैसे कोविड -19 को मिटाने एक वैक्सीन का सहारा लिया गया और उसी तरह आतंकवाद भ्रष्टाचार को समाप्त करने उसकी जड़ तक जाना होगा, जो ऐसा कर रहे हैं वही लोग आपस में त्रैमासिक सम्मेलन कर भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं लेने का हाल ढूंढे, तो इस महामारी को जीरो टॉलरेंस तक पहुंचा जा सकता है,जो भ्रष्टाचार हर जगह, एक चपरासी से लेकर बड़े ऑफिसर तक वह संत्री से लेकर मंत्री तक होने को कहा जाता है, हालांकि इसमें कुछ अपवाद भी हो सकते हैं, अगर यही आपस में त्रैमासिक सम्मेलन कर इसे जीरो टॉलरेंस तक पहुंचाने का प्रण ले तो भ्रष्टाचार देने वाले की हिम्मत नहीं होगी क्योंकि 10 से 50 पेर्सेंट तक कमीशन चलने के आरोप जन सभाओं में नेता लोग ही लगाते रहते हैं,यह सभी जानते हैं। जैसे अभी आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 7-8 नवंबर 2024 में सभी विशेषज्ञ बैठकर विचारविमर्श कर रहे हैं वैसे ही भ्रष्टाचार पर भी इस तरह का सम्मेलन होना चाहिए। मेरा मानना है कि आतंकवाद व भ्रष्टाचार को एक ही परिभाषा के दायरे में लाना ज़रूरी हो गया है यदि दोनों समाप्त हो जाएंगे तो भारत एक बार फिर त्रेतायुग की ओर चल पड़ेगा और सोने की चिड़िया कहलाएगा। चूँकि आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 7-8 नवंबर 2024 को शुरू हो गया है इसलिए मेरा मानना है कि इसी तर्ज पर भ्रष्टाचार विरोधी सम्मेलन भी रखना चाहिए जो त्रैमासिक स्तरपर हो, इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 7-8 नवंबर 2024 सराहनीय है, परंतु अब भ्रष्टाचार को आतंकवाद का पर्यायी मानना अत्यंत ज़रूरी हो गया है।

साथियों बात अगर हम नई दिल्ली में शुरू आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 7-8 नवंबर 2024 की करें तो एनआईए के तत्वावधान में गुरुवार से दिल्ली में दो दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन शुरू हो गया है,केंद्रीय गृह मंत्रीद्वारा सम्मेलन के उद्घाटनक्रर संबोधन। सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मुद्दों और आतंकवाद से उत्पन्न खतरों पर विचारविमर्श हो रहा है। पीएम के नेतृत्व में भारत सरकार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गयी है। सरकार आतंकवाद की बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध है। वार्षिक सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मुद्दों और आतंकवाद से उत्पन्न खतरों पर विचार-विमर्श हो रहा है। दो दिवसीय सम्मेलन के दौरान आतंकवाद-निरोधी जांच में अभियोजन और बदल रहे कानूनी ढांचा पर भी चर्चा हो रही है।अनुभवों और बैस्ट प्रैक्टिसिस को साझा किया जाएगा। केंद्रीय गृहमंत्री ने ने खुद सोशल साइट एक्स पर ट्वीट कर इस सम्मेलन के बारे में

बताया कि सरकार अपनी शून्य सहनशीलता की नीति के साथ आतंक मुक्त भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है।उन्होंने लिखा था कि दो दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन भारत के सुरक्षा गढ़ को मजबूत करने के लिए एजेंसियों के बीच समन्वय को और बढ़ाएगा। उभरती प्रौद्योगिकियों से संबंधित चुनौतियों और अवसरों से जुड़े मुद्दों पर भी इस सम्मेलन के दौरान चर्चा होगी,इसके साथ ही इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सहयोग और देशभर में विभिन्न आतंकवाद-निरोधी गतिविधियों पर भी चर्चा होगी।सम्मेलन में आतंकी पारिस्थितिकी तंत्र को खत्म करने की रणनीतियों सहित विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों भी विचार-विमर्श होगा। सम्मेलन का मुख्य फोकस संपूर्ण सरकार दृष्टिकोण की भावना में आतंकवाद के खतरे के खिलाफ समन्वित कार्रवाई करना है और इसके लिए चैनल स्थापित करके विभिन्न हितधारकों के बीच तालमेल विकसित करना है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सहयोग और रणनीतियों पर की जाएगी चर्चा। एनआईए द्वारा आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी, कानून, फोरेंसिक और प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ आतंकवाद से निपटने के लिए कानूनी ढांचे, अभियोजन चुनौतियों और उभरती प्रौद्योगिकियों की भूमिका जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक साथ आए। चर्चाओं में भारत भर में सक्रिय आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सहयोग और रणनीतियों पर भी चर्चा की। हितधारकों के बीच तालमेल विकसित करना है उद्देश्य गृह मंत्रालय ने कहा कि आतंकवाद विरोधी सम्मेलन-2024 का मुख्य फोकस संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण की भावना में आतंकवाद के खतरे के खिलाफ समन्वित कार्रवाई के लिए चैनल स्थापित करके विभिन्न हितधारकों के बीच तालमेल विकसित करना है। बैठक का उद्देश्य भविष्य की नीति निर्माण के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करना भी है। दो दिवसीय सम्मेलन में विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों पर विचार-विमर्श और चर्चाएं केंद्रित होंगी। जिनमें आतंकवाद-रोधी जांच में अभियोजन और कानूनी ढांचा विकसित करना, अनुभवों और अच्छे तरीकों को साझा करना, उभरती प्रौद्योगिकियों से संबंधित चुनौतियां और अवसर,अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सहयोग और भारत भर में विभिन्न आतंकवाद-रोधी थिएटरों में आतंकीपारिस्थितिकी तंत्र को खत्म करने की रणनीतियां शामिल हैं। इस सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, आतंकवाद से निपटने से संबंधित मुद्दों से निपटने वाली केंद्रीय एजेंसियों और विभागों के अधिकारी तथा कानून, फोरेंसिक और प्रौद्योगिकी जैसे संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञ भाग लिए। गृह मंत्रालय ने कहा कि वार्षिक सम्मेलन पिछले कुछ वर्षों में परिचालन बलों, तकनीकी, कानूनी और फोरेंसिक विशेषज्ञों तथा आतंकवाद से निपटने में लगी एजेंसियों के लिए एक बैठक बिंदु के रूप में उभरा है, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मुद्दों और आतंकवाद से उत्पन्न खतरों पर विचारविमर्श किया जाता है। साथियों बात अगर हम आतंकवाद व भ्रष्टाचार को एक ही परिभाषा के दायरे में लाने की करें तो, मेरा मानना है कि अब समय आ गया है कि इसका क्रियान्वयन शीघ्र तात्कालिक किया जाए, जिसकी अभी से सीधे रणनीति बनाकर टॉपअप से बॉटमअप तक व 747 जिलों से 5410 से अधिक तहसीलों तक पैनी नजर रखकर ऐसा जाल बिछाया जाए,कि एक चपरासी भी 10 रुपए की रिश्वत लेने से डरे ! जिस तरह से माननीय गृहमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ बॉडी लैंग्वेज दिखाते हैं वह अब धरातल पर तात्कालिक लाना जरूरी है, क्योंकि यह भ्रष्टाचार अर्थव्यवस्था को खोखला करने का सटीक कारण बन सकता है,जिसे हमें शीघ्र जड़ से काटकर फेंकना है, क्योंकि हमें अब जल्द 5 वीं से 3री अर्थव्यवस्था पर आना है तो, सबसे बड़ी बाधा भ्रष्टाचार को जड़ से कटकर फेंकना होगा, जिसकी जवाबदेही हर शासकीय कर्मचारी व जनता को एक साथ उठना होगा।

पब्लिक एशियाः पत्र पंजीकरण संख्याः HARHIN/2011/40057, स्वामी मुकेश वत्स के लिए मुद्रक, प्रकाशक, स्वाति वर्मा ने पब्लिक एशिया E- 33, सैक्टर-7 नोएडा, गौतमबुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित करवाकर कार्यालय पब्लिक एशिया हाउस, शॉप नो.-8 ईदगाह रोड, नियर रेलवे स्टेशन, मॉडल टाउन, पानीपत, 132103, हरियाणा से प्रकाशित किया से प्रकाशित किया। E-mail: publicasia1989@gmail.com, website: www.publicasia.in, स्वाति वर्मा (संपादक), मुख्य कार्यालय : पब्लिक एशिया हाऊस 686 जी, न्याय खंड 2 इंदरापुरम गाज़ियाबाद(उ.प्र)। Mobile No. 8287879604, 9891945513, 0120-2605513 इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होगें।
वैधानिक सूचना-पाठकों को सलाह दी जाती है की किसी विज्ञापन पर प्रतिक्रिया से पहले विज्ञापन में प्रकाशित किसी उत्पाद या सेवा के बारे में पूरी तरह उपयुक्त जांच- पड़ताल कर लें। यह समाचार पत्र उपरोक्त विज्ञापन के बारे में किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

मुख्य समाचार

जिलाधीश धीरेंद्र खडग़टा ने जारी किए आदेश

एचएसवीपी के अधिकार क्षेत्र से अनाधिकृत अतिक्रमण हटाने के दृष्टिगत ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त

पब्लिक एशिया ब्यूरो

रोहतक » जिलाधीश धीरेंद्र खडग़टा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 17(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के दौरान कानून व्यव-स्था बनाएं रखने के दौरान डयूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त करने के आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश धीरेंद्र खडग़टा द्वारा जारी किए गए आदेश के तहत 12 नवंबर को सेक्टर 26 व खरावड़ बाईपास स्थित सेक्टर 27 से अतिक्रमण हटाने के दौरान जिला राजस्व अधिकारी कनब को डयूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार 13 नवंबर को सेक्टर 4, सेक्टर 4 के एक्सटेंशन व सेक्टर 5 से अतिक्रमण हटाने के दौरान जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी राजपाल चहल को ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। जारी आदेश के तहत पुलिस अधीक्षक द्वारा डयूटी मैजिस्ट्रेट के साथ महिला पुलिस सहित पर्याप्त पुलिस तैनात किया जाएगा तथा पुलिस बल के प्रभारी निरंतर डयूटी मैजिस्ट्रेट के संपर्क में रहेंगे। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के एस्टेट ऑफिसर द्वारा कार्रवाई रिपोर्ट भी भेजना सुनिश्चित किया जाएगा।

कृषि विभाग की टीमों ने खाद विक्रेताओं की दुकानों एवं गोदामों की जांच की

एजेंसी

जालंधर » पंजाब में जालंधर के जिला उपायुक्त डॉ हिमांशु अग्रवाल द्वारा कृषि विभाग को डी.ए.पी. खाद विक्रेताओं की लगातार जांच करने के दिए गए सख्त निर्देश के बाद विभाग ने आज खाद विक्रेताओं की 10 दुकानों और गोदामों की जांच की गई और छह नमूने भरने के अलावा दुकानों में पड़ी खाद की भी जांच की। विकासखंड कृषि अधिकारी डॉ सुरजीत सिंह ने गुरुवार को बताया कि जांच के दौरान भरे गये नमूनों को जांच के लिये लेबोरेट्री में भेजा जायेगा और रिपोर्ट आने के बाद उसके अनुसार कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान उर्वरक विक्रेताओं को स्टॉक बोर्ड पर प्रतिदिन उर्वरक का स्टॉक एवं रेट लिखने तथा किसानों को जो भी कृषि सामग्री बेची जाती है उसका पक्का बिल काटने तथा अनावश्यक सामान खाद के साथ न देने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि यह अभियान आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा और यदि कोई उर्वरक विक्रेता/डीलर बिना बिल के उर्वरक, दवा या बीज बेचता पाया गया तो उसके खिलाफ उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत कानूनी कार्रवाई की जायेगी। डॉ.सिंह ने बताया कि गेहूं की खेती के लिये फास्फोरस खाद्य तत्व की आवश्यकता होती है, जिसके लिये किसान बिजाई के समय डीएपी उर्वरक का प्रयोग करते है।

कनाडा हो या भारत सिख किसी भी धार्मिक स्थल पर हमला नहीं कर सकता : ब्रह्मपुरा

एजेंसी

तरनतारन » शिरोमणि अकाली दल के उपाध्यक्ष, विधान सभा क्षेत्र खडूर साहिब के प्रभारी और पूर्व विधायक रविंदर सिंह ब्रह्मपुरा ने गुरुवार को कहा कि कनाडा में धार्मिक स्थलों पर हाल ही में हुई शरारतों की आड़ में सिख समुदाय को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। ब्रह्मपुरा ने दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों जस्टिन ट्रूडो और नरेन्द्र मोदी से विचारवान और ईमानदार किया। उन्होंने कहा कि सिख स्वाभाविक रूप से सभी पूजा स्थलों का सम्मान करते हैं और धार्मिक स्थलों पर हमलों में किसी भी तरह की संलिप्तता को अस्वीकार करते हैं। ब्रह्मपुरा ने भारत में 1984 के सिख नरसंहार के बाद सिखों के लिये न्याय की कमी की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। उन्होने कहा कि सिख समुदाय न्याय के लिये धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा है, जो बहुत लंबे समय से विलंबित है। ब्रह्मपुरा ने सिख मूल्यों के प्रति उनकी दृढ़ प्रतिबद्धता के लिये श्री अकाल तख्त साहिब और जत्थेदार साहिबों की सराहना की, साथ ही शांति के दृढ़ संवर्धक के रूप में उनकी भूमिका के लिये सिखों की भी सराहना की।

कौर ने पुस्तक मेला में तीन पुस्तकों का विमोचन किया

एजेंसी

चंडीगढ़ » महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (मदवि) रोहतक में आयोजित तीन दिवसीय पुस्तक मेला में गुरूवार को दूसरे दिन मुख्यातिथि भारतीय पुनर्वास परिषद की अध्यक्षा डॉ शरणजीत कौर ने तीन पुस्तकों का विमोचन किया। सुश्री कौर ने इस अवसर पर कहा कि किताबों में जीवन का सार होता है, जिसमें लेखक अपने जीवन के अनुभव को साझा करते हैं। उन्होंने कहा कि जीवन में अच्छा इंसान बनने के लिये संवेदनशील होना होगा और किताबें इंसान को संवेदनशील बनाती हैं। उन्होंने युवाओं से किताबों से जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मदवि का पुस्तक मेला नवोदित लेखकों के लिये अहम मंच बन चुका है। यह पुस्तक मेला नये कवियों और लेखकों को प्रोत्साहन दे रहा है, ऐसा मुख्य अतिथि का कहना था। प्रतिष्ठित शिक्षाविद डॉ सीता राम व्यास ने इस कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि शिरकत की। इस तीन दिवसीय पुस्तक मेला में आज डॉ रमा कांता की पुस्तक विप्लव गान, डॉ चंद्र दत्त की पुस्तक डॉ मधुकांत के काव्य का समीक्षात्मक अध्ययन तथा नेहा धनखड़ की पुस्तक बंजर मन का लोकार्पण डॉ शरणजीत कौर ने किया।

प्रमोद कुमार ने रेल डिब्बा कारखाना, कपूरथला के महाप्रबंधक का अतिरिक्त प्रभार संभाला

एजेंसी

कपूरथला » पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स (पी एल डब्ल्यू), के प्रमुख मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (पी सी ए ओ) प्रमोद कुमार ने गुरुवार को रेल डिब्बा कारखाना (आर सी एफ), कपूरथला के महाप्रबंधक का अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया। नागपुर विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक, श्री प्रमोद कुमार 1986 बैच के भारतीय रेलवे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स सेवा के अधिकारी हैं, जिन्होंने 1990 में भोपाल में रेलवे विद्युतीकरण परियोजना के कार्यान्वयन में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। नवंबर 2017 में नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ओवर हेड इक्विपमेंट को सीधे विद्युत ऊर्जा प्रदान करने वाली एक अभूतपूर्व पांच किलोवाट सौर पैनल प्रणाली के कार्यान्वयन के साथ, स्थिरता और नवाचार के प्रति श्री कुमार की प्रतिबद्धता नयी ऊंचाइयों पर पहुंच गयी।

नशे के खिलाफ दीप से दीप जलाने की जरूरत : मनोज सांगवान

जाट कॉलेज में एचआईवी एड्स और नशे पर हुआ विशेष व्याख्यान

सुकरमपाल, पब्लिक एशिया

रोहतक » अखिल भारतीय जाट सूरमा स्मारक महाविद्यालय में एनसीसी द्वारा वीरवार को 'युवा एवं नशा' विषय पर विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता कलस्टर प्रोग्राम मैनेजर, डीआईएसएचए (दिशा), जींद के मनोज सांगवान रहे। मुख्य वक्ता का कॉलेज प्राचार्या डॉ. शबनम राठी एवं एनसीसी ऑफिसर लेफ्टिनेंट डॉ. विवेक दांगी ने स्वागत किया। संचालन डॉ. मीतू भारती ने किया। मनोज सांगवान ने विद्यार्थियों को नशा ना करने का संकल्प भी दिलवाया। मुख्य वक्ता मनोज सांगवान ने वालिंटियर्स को संबोधित करते हुए कहा कि नशा आज गंभीर समस्या बन गई है। इससे कई परिवार और जिंदगी बर्बाद हो रही है। खासकर युवा पीढ़ी पर इसका ज्यादा असर देखा जा रहा है। निरंतर बढ़ते नशे के प्रचलन से युवा पीढ़ी खोखली होती जा रही है। उन्होंने कहा कि नशा शब्द छोटा है मगर यह कई पीढ़ियों के जीवन को प्रभावित और खत्म कर देता है। उन्होंने बताया कि जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही जो युवक नशे की लत का शिकार हो रहे हैं, उन्हें अब एचआइवी (एड्स का वायरस) का डंक भी लग रहा है। इंजेक्शन से नशा करने वाले युवा एचआइवी के शिकार हो रहे हैं। एक तरफ नशा फैल रहा है तो उसके साथ-साथ एचआइवी भी पांव पसार रहा है। दरअसल, अब तक तो असुरक्षित यौन संबंध ही एड्स के वायरस एचआइवी के फैलने का कारण बन रहा था, मगर नए आंकड़ों के मुताबिक इंजेक्शन से नशा करना युवाओं में एचआइवी के फैलने का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। कॉलेज प्राचार्या डॉ. शबनम राठी ने विद्यार्थियों को जागरूक करते हुए कहा कि नशा एक ऐसी बीमारी है जोकि पूरे परिवार को तहस-नहस कर देती है। इसलिए विद्यार्थियों को स्वयं को नशे से दूर रहकर दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उन्होंने बताया कि यह एक धीमा जहर है जो सर्वप्रथम एक नशेड़ी के शरीर, उसके धन व घर की सुख-शांति पर कड़ा प्रहार कर जीवन का नाश कर देता है। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से युवा पीढ़ी जोकि स्वयं व देश की भाग्य विधाता है। उन्हें इनसे दूर रहने के लिए प्रेरित करना होगा। इस अवसर पर डॉ. विवेक दांगी, डॉ. मीतू भारती, डॉ. नीरा, डॉ. लक्ष्मी दांगी, डॉ. दीपक सहित सभी एनसीसी वालिंटियर्स उपस्थित रहे।

डीएपी की कालाबाजारी, जमाखोरी और तस्करी बर्दाश्त नहीं, होगी सख्त कार्रवाई

एजेंसी

सोनीपत » हरियाणा के सोनीपत उपजिलाधिकारी (एसडीएम) अमित कुमार ने गुरुवार को कहा कि डीएपी खाद की कालाबाजारी, जमाखोरी और तस्करी को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। श्री कुमार ने कहा कि जिले में डीएपी के वितरण में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, इसके साथ-साथ किसानों को डीएपी के साथ जबरन गेहूं बीज और अन्य कोई कीटनाशक आदि न थोपा जाए। उन्होंने कहा कि किसानों से निर्धारित कीमत से अधिक वसूलने वालों पर भी संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी।सोनीपत क्षेत्र में डीएपी की आपूर्ति को लेकर एसडीएम ने आज लघु सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में सभी प्राईवेट डीलरों, पैक्स संचालकों, कृषि विभाग सहित खाद वितरण से जुड़ी सभी एजेंसी संचालकों के साथ बैठक की। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि डीएपी की कालाबाजारी को रोकने के लिए निरंतर खाद वितरित करने वाली दुकानों और उनके गोदामों की चैंकिग करें ताकि कहीं भी डीएपी की कालाबाजारी न हो। उन्होंने दुकानदारों को निर्देश दिए कि वे न तो डीएपी का स्टॉक करेंगे और उनके पास डीएपी लेने के लिए आने वाले किसानों को डीएपी के साथ गेहूं बीज या अन्य कीटनाशक आदि दवाई लेने के लिए दबाव नहीं बनाएंगे अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी और उनका लाईसेंस रद्द कर दिया जाएगा।

डीएपी खाद न मिलने से परेशान किसान ने कीटनाशक खाकर आत्महत्या की

एजेंसी/हिसार » हरियाणा में हिसार जिला के उकलाना क्षेत्र में बुधवार को डीएपी न मिलने से परेशान होकर एक 35 वर्षीय किसान ने नयी अनाज मंडी में कीटनाशक खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने किसान को इलाज के लिये सामान्य अस्पताल (उकलाना) में भेजा। यहां से चिकित्सकों ने बरवाला रेफर कर दिया। गुरुवार सुबह शव का हिसार के नागरिक हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम किया गया और परिजनों को सौंप दिया गया। जानकारी के अनुसार, रामभगत डीएपी के लिये कई दिनों से परेशान था। किसान रामभक्त डीएपी लेने के लिये उकलाना की अनाज मंडी में आया हुआ था, लेकिन यहां पर डीएपी नहीं मिल पाई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि रामभक्त डीएपी न मिलने से परेशान था।

कुल्लू से आनी को जोड़ने वाली जलोड़ी टनल का बदलेगा नक्शा

एजेंसी

शिमला » हिमाचल प्रदेश में प्रस्तावित जलोड़ी टनल के मार्ग का नक्शे (अलाइनमेंट) को संशोधित किया जाएगा। वहीं, टनल की लंबाई को समीक्षा की जायेगी। हालांकि सोझा के ग्रामीणों की ओर से जलोड़ी टनल को लेकर आपत्ति जताई गई थी। कुल्लू के बाह्य सराज को जोड़ने वाली प्रस्तावित जलोड़ी टनल की लंबाई की समीक्षा की जायेगी। इसके अलाइनमेंटको भी संशोधित किया जाएगा। इसके लिए सर्वे का काम दिल्ली की एक कंपनी अल्टीनॉक को एनएच की ओर से सौंपा गया है। इसका प्रस्ताव भी तैयार किया गया है। हालांकि, प्रस्ताव को अभी तक सरकार की ओर से मंजूरी मिलने का इंतजार है। स्वीकृति मिलने के बाद कंपनी की ओर से जलोड़ी टनल की लंबाई और अलाइनमेंट को संशोधित करने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

गौरतलब है कि महाराष्ट्र की जिस कंपनी की ओर से पहले जलोड़ी टनल की डीपीआर तैयार की गई थी। उसके मुताबिक जलोड़ी टनल की लंबाई 4.2 किलोमीटर थी और इसकी लागत 364.65 करोड़ की थी। टनल घियागी-सजवाड़ के मध्य से जलोड़ी के दूसरी तरफ निकलनी थी। अब घियागी से तीन किलोमीटर ऊपर सोझा से नीचे टनल का एक मुहाना शुरू होगा। यह जलोड़ी दर्रा के दूसरी तरफ कंडुगाड़ में जाकर निकलेगा।

सोझा के ग्रामीणों की ओर से जलोड़ी टनल को लेकर आपत्ति जताई गई थी। ग्रामीणों का मानना है कि टनल के निर्माण के बाद उनके जल स्रोत पूरी तरह सूख जाएंगे। इसके बाद एनएच अथॉरिटी की ओर से ग्रामीणों की बात को परिवहन मंत्रालय के समक्ष रखा गया। परिवहन मंत्रालय ने देशभर में अन्य टनलों का हवाला देते हुए इस पर अधिक दिलचस्पी नहीं दिखाई।

सहायक अभियंता, एनएच-305 टहल सिंह ने बताया कि जलोड़ी टनल की लंबाई और टनल की अलाइनमेंट को संशोधित किया जाना है। इसका काम दिल्ली की अल्टीनॉक कंपनी को दिया गया है। हालांकि, इसकी अभी तक अनुमोदन नहीं हुआ है।

गुमशुदा पुत्री के अभिभावक धरने पर बैठे

एजेंसी/हिसार » हरियाणा में हिसार शहर से एक 16 वर्षीय लड़की के लगभग सवा महीने से गायब होने से परेशान अभिभावक गुरुवार को जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। डीसी कॉम्प्लेक्स के सामने धरने पर बैठे शहर के आज़ाद नगर क्षेत्र की गीता कॉलोनी के निवासी सुनील सोनी ने बताया कि उनकी बेटी हर्षिता 29 सितम्बर से लापता है। उन्होंने आज़ाद नगर पुलिस चौकी में शिकायत दी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।उन्होंने कहा कि वह कई बार अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। श्री सोनी ने कहा कि अब वह किसी से नहीं मिलेंगे, लेकिन उनकी पुत्री नहीं मिली तो धरनास्थल पर ही जहर खा लेंगे। श्री सोनी के साथ उनकी पत्नी रागनी और दो छोटे बच्चे भी धरने पर बैठे हैं।

कांग्रेस जम्मू-कश्मीर में फिर से लाना चाहती है आतंकवाद, अलगाववाद का काला दौर : भाजपा

एजेंसी

शिमला » हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल एवं मुख्य प्रवक्ता राकेश जमवाल ने गुरुवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस जम्मू-कश्मीर में फिर से आतंकवाद और अलगाववाद का काला दौर लाना चाहती है।

श्री बिंदल और श्री जमवाल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 और 35ए को फिर से लाने के नेशनल कांफ्रेंस (नेकां) के प्रस्ताव का समर्थन कर कांग्रेस ने देश को तोड़ने का कुचक्र फिर से चल दिया है। प्रस्ताव में कहा गया है- विशेष राज्य का दर्जा और संवैधानिक गारंटियां महत्वपूर्ण हैं। यह जम्मू-कश्मीर की पहचान, संस्कृति और लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करता है। विधानसभा इसे एक तरफा हटाने पर चिंता व्यक्त करती है। केन्द्र सरकार राज्य के विशेष दर्जे को लेकर यहां के प्रतिनिधियों से बात करे। इसकी संवैधानिक बहाली पर काम किया जाए। विधानसभा इस बात पर जोर देती है कि यह बहाली नेशनल यूनिटी और जम्मू-कश्मीर के लोगों की इच्छाओं, दोनों को ध्यान में रख कर की जाए।

भाजपा के दोनों (बिंदल और जमवाल) नेताओं ने कहा कि बुधवार को विधानसभा में जो भी कुछ हुआ, वह पाकिस्तान और देश विरोधी लोगों को खुश करने के लिए किया गया, जम्मू-कश्मीर की जनता को गुमराह करने के लिए किया गया। आज जो देश की एकता के लिए खड़े हैं, जम्मू-कश्मीर वे विकास और शांति के पक्ष में खड़े हैं, उन्हें मार्शल के जरिये बेरहमी से जम्मू-कश्मीर विधानसभा से बाहर निकाला जा रहा है। कांग्रेस-नेकां, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) - ये सब केन्द्रशासित प्रदेश में फिर से आतंकवाद को लाना चाहते हैं। यह कांग्रेस और नेकां का राष्ट्रविरोधी एजेंडा है। उन्होंने कहा कि शेख अब्दुल्ला से लेकर उमर अब्दुल्ला तक, भावनात्मक ब्लैकमेल करना नेकां की दिनचर्या है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और नेकां और पीडीपी ये सब कश्मीर घाटी की शांति से परेशान हैं। ये जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद के काले दौर को वापस लाना चाहती है। हमारी सरकार ने वादा किया था कि जम्मू-कश्मीर को विधानसभा देंगे, चुनाव करायेंगे, केवल पांच साल के अंदर मोदी सरकार ने चुनाव कराये और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल किया। हम आगे भी जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए काम करेंगे।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस फिर से अनुच्छेद 370 बहाल करके यह बताना चाहती है कि हम वाल्मीकियों, गोरखा समाज, पश्चिमी पाकिस्तान शरणार्थी, पहाड़ी और गुर्जर के खिलाफ हैं। कांग्रेस ने नेकां के घोषणापत्र का समर्थन कर जम्मू-कश्मीर में आरक्षण को ख़त्म करने का समर्थन किया था। वैसे भी कांग्रेस नेता राहुल गाँधी अमेरिका जाकर आरक्षण को ख़त्म करने की बात कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के हटने के बाद आतंकवाद की घटनाओं में 70 प्रतिशत की कमी आई है। नागरिकों की मृत्यु में भी लगभग 80 प्रतिशत की कमी आई है। विदेशी नागरिकों के पर्यटन में 300 प्रतिशत का उछाल आया है। जम्मू-कश्मीर का बजट 17 प्रतिशत बढ़ा है। पत्थरबाजी की घटना बिलकुल बंद हो गई। आतंकवादी घटनाएं दो-तीन जिलों में ही सिमट कर रह गई। जहाँ पहले पांच-सात प्रतिशत मतदान होता था, वहां भी 50 प्रतिशत मतदान होने लगा। जो पहले अलगाववाद और आतंकवाद की वकालत कर रहे थे, वे भी अब हिंदुस्तान के संविधान के आईन में लोकतंत्र को मजबूती देते हुए वोट मांगते दिखाई दिए।

मीडिया से आई जानकारी में पता चला है कि जम्मू-कश्मीन स्पीकर ने स्वयं मंगलवार (5 नवंबर) को मंत्रियों की बैठक बुलाई थी और खुद ही प्रस्ताव तैयार किया। ये सरासर असंवैधानिक है। ये प्रस्ताव लाना पहले से सदन की कार्यवाही की सूची में नहीं था। जब विधानसभा के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी तो प्रस्ताव कैसे लाया गया?

इस प्रस्ताव को बिना किसी बहस के पारित कर दिया गया क्योंकि स्पीकर ने शोरगुल के बीच इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया। इतने बड़े विषय पर चर्चा नहीं होने दी गई। ये कैसा लोकतंत्र है? इस प्रस्ताव की कोई कानूनी वैधता नहीं है क्योंकि जम्मू-कश्मीर विधानसभा संसद या उच्चतम न्यायालय से ऊपर नहीं है। कोई भी विधानसभा अनुच्छेद 370 और 35ए को वापस नहीं ला सकती।

जम्मू-कश्मीर में फिर से आतंकवाद लाना चाहती है कांग्रेस» बड़ौली

चंडीगढ़ » हरियाणा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष पंडित मोहन लाल बड़ौली ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुये गुरुवार को कहा कि कांग्रेस जम्मू-कश्मीर में फिर से आतंकवाद और अलगाववाद का काला दौर लाना चाहती है। श्री बड़ौली ने कहा कि जम्मू- कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 और 35ए को फिर से लाने के नेशनल कांफ्रेंस के प्रस्ताव का समर्थन कर कांग्रेस ने देश को तोड़ने का कुचक्र फिर से चला दिया है। हाल ही में जम्मू- कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 का बैनर दिखाये जाने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुये श्री बड़ौली ने कहा कि जम्मू- कश्मीर विधानसभा में जो भी कुछ हुआ, वह पाकिस्तान और देश विरोधी लोगों को खुश करने और जम्मू-कश्मीर की जनता को गुमराह करने के लिये किया गया। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा देश की संसद और उच्चतम न्यायालय से ऊपर नहीं है। कोई भी विधानसभा अनुच्छेद 370 और 35ए को वापस नहीं ला सकती। अनुच्छेद 370 और 35ए इतिहास बन चुकी है, इस इतिहास को अब कोई बदल नहीं सकता। नेशनल कांफ्रेंस जम्मू-कश्मीर के लोगों को गुमराह कर रही है।

पंजाब सरकार 'पंजाब विवाद समाधान एवं मुकदमेबाजी नीति 2020' के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये प्रतिबद्ध

एजेंसी

चंडीगढ़ » पंजाब सरकार जनहित में 'पंजाब विवाद समाधान एवं मुकदमेबाजी नीति 2020' के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये प्रतिबद्ध है।

पंजाब सरकार के प्रवक्ता ने गुरुवार को बताया कि यह नीति अदालतों में लंबित मामलों और बैकलॉग को संबोधित करती है, क्योंकि समस्या जटिल है और इसके समाधान के लिये बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। अदालतों के समक्ष मुकदमों का एक बड़ा हिस्सा भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले निकायों जैसे सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, वैधानिक निगम, सरकारी कंपनियां आदि और इस तरह की अन्य संस्थाओं के खिलाफ रिट कार्यवाही से जुड़ा है। इसलिये पंजाब सरकार द्वारा यह विवाद समाधान और मुकदमेबाजी नीति तैयार की गई है क्योंकि यह मान्यता है कि सरकार और ऐसी राज्य संस्थायें अदालतों और अर्ध न्यायिक अधिकारियों के समक्ष मुकदमेबाजी के एक बड़े हिस्से में एक पक्ष हैं और ऐसी स्थितियां बनाना आवश्यक है, जो मामलों की स्थापना को कम से कम करें और मुकदमेबाजी के निपटारे में देरी को कम करें।

नीति यह सुनिश्चित करने का भी प्रयास करती है कि राज्य और ऐसी सभी राज्य संस्थाएँ भविष्य में मुकदमेबाजी को कम करने के लिए प्रभावी ढंग से काम करें और चल रहे मुकदमेबाजी में किसी भी तरह की देरी में योगदान न दें। राज्य और ऐसी राज्य संस्थायें, जहां संभव हो, प्रशासनिक रूप से या वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली के माध्यम से सरकार के साथ विवादों के समाधान को प्रोत्साहित करेंगी ताकि सभी विवादों को अंतिम निर्णय के लिए अदालतों पर न छोड़ा जाये।

नीति में यह प्रावधान है कि राज्य मुकदमेबाजी के कुशल प्रबंधन को सुनिश्चित करेगा और खुद को एक जिम्मेदार मुकदमेबाज के रूप में संचालित करेगा। राज्य अदालतों के समक्ष नए विवादों को कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाएगा। कर्मचारियों को राज्य के स्तर पर या वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली के माध्यम से विवादों को निपटाने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

अधिकारियों को हितधारकों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात स्थापित कानून के अनुसार सुविचारित, स्पष्ट आदेश पारित करने के लिये प्रशिक्षित किया जायेगा। राज्य अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचने का प्रयास करेगा, विशेषकर जहां वित्तीय प्रभाव दो लाख रुपये से कम है; जब तक कि इसमें कानून या नीति का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल न हो, सक्षम प्राधिकारी निर्धारित समय अवधि के भीतर वसूली योग्य बकाया के संबंध में स्पष्ट आदेश पारित करेगा।

नीति में यह भी प्रावधान है कि सेवा मामलों में सामान्य रूप से कोई अपील दायर नहीं की जाएगी जहां निर्णय किसी तुच्छ मामले पर हो और कोई मिसाल कायम न करता हो और व्यक्तिगत शिकायत से संबंधित हो, निर्णय किसी सिद्धांत को शामिल किए बिना और कोई मिसाल कायम किए बिना पेंशन या सेवानिवृत्ति लाभ के मामले से संबंधित हो। इसी तरह, राजस्व मामलों में अपील सामान्य रूप से दायर नहीं की जायेगी, यदि मामले का वित्तीय निहितार्थ 15 लाख रुपये से कम है। दो लाख रुपये तक की छूट दी जायेगी, जब तक कि इसमें कानून या नीति का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल न हो, यदि मामला उच्च न्यायालयों के निर्णयों के अंतर्गत आता है, जिन्होंने इस क्षेत्र में अपना विचार रखा है और जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है, या सर्वोच्च न्यायालय का है और वर्तमान मामले को उन मामलों के तथ्यों से अलग नहीं किया जा सकता है।नीति में यह भी प्रावधान है कि विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि अपील, आवेदन, लिखित बयान और जवाब निर्धारित समय के भीतर न्यायालयों के समक्ष दायर किये जायें ताकि इन तकनीकी आधारों पर स्थगन से बचा जा सके। अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जानी चाहिये। नीति में यह भी प्रावधान है कि सेवा मामलों में सामान्यतः कोई अपील दायर नहीं की जायेगी, जहां निर्णय किसी तुच्छ मामले पर हो तथा कोई मिसाल कायम न करता हो तथा व्यक्तिगत शिकायत से संबंधित हो, निर्णय किसी सिद्धांत को शामिल किए बिना तथा कोई मिसाल कायम किये बिना पेंशन या सेवानिवृत्ति लाभ के मामले से संबंधित हो।

मंडियों में अनाज की अधिकता से निपटने में पंजाब सरकार विफल : दहिया

एजेंसी

फगवाड़ा » पंजाब कांग्रेस प्रवक्ता और नकोदर विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी डॉ. नवजोत सिंह दहिया ने केंद्र और पंजाब सरकार पर पंजाब की अनाज मंडियों में धान की आमद को नियंत्रित करने में विफल रहने का आरोप लगाया।

डॉ दहिया ने कहा कि व्यापक योजना और वादों के बावजूद, राज्य की अनाज मंडियों में अनाज भंडारण की कोई उचित व्यव-स्था नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य की अनाज मंडियां खचाखच भरी हुई हैं, जिससे किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें अपनी कटी हुई धान को रखने के लिये पर्याप्त जगह नहीं मिल पा रही है। उन्होंने हाल ही में हुये पंचायत चुनावों के दौरान सरकार द्वारा कथित तौर पर अपनाई गयी बलपूर्वक रणनीति की ओर भी ध्यान आकर्षित किया, जहां उनका दावा है कि कई उम्मीदवारों को दबाव का सामना करना पड़ा, जिससे जनता के बीच सरकार की प्रतिष्ठा और खराब हुई। जैसे-जैसे स्थिति बिगड़ती जा रही है, केंद्र और पंजाब दोनों सरकारों को किसानों की बढ़ती आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, जो अब उनके कल्याण के लिये नेतृत्व की प्रतिबद्धता पर सवाल उठा रहे हैं।

सड़क दुर्घटना में बुजुर्ग की मौत

एजेंसी

हिसार » हरियाणा में हिसार जिला के हांसी में गुरुवार सुबह एक बाइक सवार बुजुर्ग को किसी अज्ञात वाहन टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गयी। पुलिस एवं परिजनों के अनुसार सीसे बोलना निवासी प्रदीप (62) अपनी पुत्री को गगन खेड़ी बस स्टैंड पर छोड़ने के बाद घर लौट रहे थे। गगन खेड़ी बिजली घर के नजदीक किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया। किसी राहगीर ने प्रदीप के परिजनों को घटना की सूचना दी। प्रदीप के परिजन मौके पर पहुंचे और शव को हांसी के नागरिक अस्पताल में लाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रहीं है।

मुख्य समाचार

5 दिसम्बर को हरियाणा स्टेट पेंशनर्स समाज का राज्य स्तरीय चुनाव

पब्लिक एशिया ब्यूरो

रोहतक » राज्य प्रधान देवराज नांदल ने एक प्रेस बयान जारी करते हुए चुनाव अधिवेशन की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि हरियाणा स्टेट पेंशनर्स समाज का राज्य स्तरीय कार्यकारिणी का चुनाव 5 दिसम्बर को सीनियर सिटीजन क्लब भवन मानसरोवर पार्क रोहतक में सुबह 10 बजे कराने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि 30 नवम्बर तक सभी जिले अपनी अपनी जिला कार्यकारिणी की सूची स्टेट कमेटी को जरूर भेज दें ताकि स्टेट कमेटी का चुनाव ठीक से हो सकें। राज्य प्रधान देवराज नांदल बताया कि चुनाव अधिवेशन की तैयारी और देखरेख के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है जिसमें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भलेराम प्रधान, महासचिव ईश्वर सिंह सैनी और एडिशनल प्रधान महासचिव वीरेंद्र शर्मा को शामिल किया गया है। वीरेंद्र शर्मा इस कमेटी के संयोजक बनाए गए हैं जो सभी जिलों की नई कार्यकारिणी की सूची का रिकार्ड रखेंगे। अधिवेशन में चुनाव के साथ-साथ हरियाणा स्टेट पेंशनर्स समाज का मांग पत्र हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी को भेजा जाएगा और मांगे मनवाने के लिए आगे की रणनीति पर विचार किया जायेगा। इस अवसर पर देवराज नांदल, चेयरमैन मेहर सिंह नैन, वीरेन्द्र शर्मा, देबी सिंह, राजेंद्र सैनी, कंवर सिंह, दयानंद यादव, रामरती देवी, रोशनी देवी, शमशेर सिवाच, बिशम्बर भाटिया, प्रीतम भयाना, धनपति हुड्डा, धर्मबीर सैनी, दयानंद सैनी आदि उपस्थित रहे।

रेडक्रॉस के रक्तदान शिविर में 51 युवाओं ने दिया रक्तदान

पब्लिक एशिया ब्यूरो

रोहतक » जिला उपायुक्त एवं जिला रेडक्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष धीरेंद्र खड़ग़टा के मार्गदर्शन में वीरवार को स्थानीय रेडक्रॉस भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में लगभग एक सौ युवाओं ने अपना पंजीकरण करवाया और जरूरत के अनुरूप 51 युवाओं ने प्रथम चरण में रक्त का दान किया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ हरियाणा रेडक्रॉस चंडीगढ़ सीएसआर कमेटी के वाइस चेयरमैन संजय मिगलानी एवं महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी वाईआरसी कॉर्डिनेटर डॉ. अंजू धीमान ने संयुक्त रूप से किया।

डीसी एवं जिला रेडक्रॉस सोसायटी के अध्यक्ष धीरेंद्र खड़ग़टा के मार्गदर्शन में रेडक्रॉस भवन में आयोजित हुआ रक्तदान शिविर

इस अवसर पर वाइस चेयरमैन संजय मिगलानी ने कहा कि रोहतक रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा रक्तदान को लेकर बेहतर प्रयास किए जा रहे है। इनका समाज में बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि वो उपायुक्त के नेतृत्व मे रेडक्रॉस सोसाइटी के साथ मिलकर कुछ ऐसी गतिविधियां जो प्रॉफिट नो लॉस पर शुरू करेंगे, जिसका लाभ जरूरतमंद गरीब लोगों को मिल सके। उन्होंने कहा कि जरूरत के समय रक्तदान से असहाय व्यक्ति का जीवन बचाया जा सकता है जिसके लिए रेडक्रॉस सोसाइटी आमजन को साथ लेकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन एवं रेडक्रॉस समिति द्वारा जो कार्य किया जा रहे हैं, इसी के चलते वे रेडक्रॉस सोसाइटी के लाइफ मेंबर बने। इस अवसर पर रेडक्रॉस सचिव श्याम सुंदर और जिला प्रशिक्षण अधिकारी रवि दत्त ने आगंतुकों और मेहमानों का स्वागत किया। इस अवसर पर विभिन्न सामाजिक संगठनों से आजीवन सदस्य जेपी गौड़, मिथलेस, लतेश, कमलेश, टी आई टीम से प्रोजेक्ट मैनेजर प्रीति, तान्या, सालू, स्वीटी, आशीष, फर्स्ट एड लेक्चरर विष्णु मित्र सैनी सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे।

झूठे दावे करने की बजाय किसानों को खाद मुहैया कराए सरकार : दीपेंद्र हुड्डा

सुकरमपाल, पब्लिक एशिया

रोहतक » सांसद दीपेंद्र हुड्डा आज रोहतक में कई सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल हुए और लोगों से मिलकर उनका हाल-चाल जाना। इस दौरान वे पूर्वांचल एकता सेवा समिति द्वारा आयोजित छठ पूजा कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने प्रदेश भर में खाद किल्लत पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि बीजेपी सरकार जानबूझकर खाद की किल्लत पैदा कर रही है। सरकार पर्याप्त खाद होने के झूठे दावे कर रही है। जबकि सच्चाई ये है कि खाद के लिए लम्बी-लम्बी लाइनें लगी हुई है और कई जगहों पर किसानों के साथ मारा-मारी की ख़बरें भी आ रही हैं। एक तरफ सरकार कह रही है कि खाद की कोई कमी नहीं है जबकि किसान एक-एक बैग खाद के लिए तरस रहे हैं और धक्का-मुक्की, हाथापाई और लाठीचार्ज के शिकार हो रहे हैं। सरकार को बताना चाहिए कि अगर खाद पर्याप्त मात्रा में मौजूद है तो किसानों को मिल क्यों नहीं रही? दीपेन्द्र हुड्डा ने मांग करी कि सरकार झूठे दावे करने की बजाय किसानों को पर्याप्त खाद मुहैया कराए। समय पर खाद किसानों का हक है।

उन्होंने किलोई हलके के गाँव असन, कलानौर हलके के गाँव बलियाना, रोहतक के पारा मोहल्ला, शीतल नगर, गाँव गुढान आदि में लोगों से मुलाक़ात की। दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि हर फसली सीजन में यही कहानी दोहराई जाती है। किसानों को लंबी-लंबी कतारों में कई-कई घंटे, कई-कई दिन इंतजार करना पड़ता है। प्रदेशभर में खाद किल्लत से किसान त्रस्त हैं। सरकार के निकम्मेपन की वजह से किसानों को खाद के लिए कतारों में धक्के खाने पड़ रहे हैं। वे अपने परिवार, बच्चों के साथ रात-रात भर खाद के लिये लाईनों में लग रहे हैं फिर भी उन्हें जरुरत भर की खाद नहीं मिल रही है। सरकार बताए कि किसान अगली फसल की बुआई करे या खाद के लिए लाइन लगाए। उन्होंने कहा बुआई के टाइम पूरी खाद नहीं, कटाई के टाईम पूरी खरीद नहीं। खरीद के टाइम किसान को रूक्क नहीं। किसान इस बात से दुःखी है कि पर्याप्त खाद नहीं मिली तो उसकी फसल का क्या होगा।

पंजाब के किसानों से तीन काले कानूनों का बदला लेने के लिए भाजपा की केंद्र सरकार कर रही है साजिश : कंग

एफसीआई क्वालिटी चेक करके चावल खरीदती है तो कर्नाटक की एफसीआई डिवीजन ने सैंपल फेल कैसे किए? : कंग

बीजेपी का मकसद तीन काले कानूनों को पीछे के दरवाजे से लागू करना है : कंग

पब्लिक एशिया ब्यूरो

चंडीगढ़ » कर्नाटक में पंजाब के चावल सैंपल को रिजेक्ट करने पर आप आदमी पार्टी (आप) ने कहा कि हर साल धान खरीद से पहले एफसीआई उसकी क्वालिटी की जांच करती है और सारे मापदंडों पर खरा उतरने के बाद ही खरीदती है, फिर कर्नाटक की एफसीआई डिवीजन ने सैंपल फेल कैसे किए?

'आप' सांसद और पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता मलविंदर सिंह कंग ने कहा कि कर्नाटक ने पंजाब के चावलों को लेकर जो कहा है उसे देखकर स्पष्ट तौर पर लगता है कि पंजाब के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रही है। उन्होंने कहा कि इस साल केंद्र सरकार एमएसपी पर

पंजाब का धान खरीदने से कतरा रही है और तरह-तरह के बहाने बना रही है। ये सब केवल पंजाब से धान न खरीदने के बहाने हैं।

दरअसल ये सब काले कृषि कानूनों के खिलाफ हुए किसान आंदोलन का बदला लेने के लिए किया जा रहा है। कंग ने पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह के पूर्व में दिए बयान का जिक्र किया कि 'भाजपा सरकार लंबे समय तक एमएसपी नहीं देगी'।

उन्होंने कहा कि भारत सरकार की इस मुद्दे को लेकर मंशा शक के घेरे में है। भाजपा काले कृषि कानूनों को पीछे के दरवाजे से लागू करना चाह रही है। एमएसपी को लेकर शुरू से ही केंद्र सरकार की मंशा में खोट रही है और उनके मंत्रियों के पूर्व में दिए बयानों से साफ जाहिर भी होता है। कंग ने कहा कि इस घटना से भारत सरकार का किसानों के प्रति नकारात्मक रवैया फिर से उजागर हुआ है। यह सिर्फ पंजाब के किसानों को परेशान करने और बदला लेने की साज़िश है।

जिला के गांवों में फसल कटाई प्रयोगों का कार्य करने पहुंचे विभाग के संयुक्त निदेशक ओपी गोदारा

सुकरमपाल, पब्लिक एशिया

रोहतक » प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आज कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सयुंक्त निदेशक ओम प्रकाश गोदारा, दो दिवसीय दौरे पर रोहतक जिला के गांवों में फसल कटाई प्रयोगों का निरिक्षण करने पंहुचे। कृषि विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा फसल कटाई प्रयोगों का कार्य किया जा रहा है। सयुंक्त निदेशक ओम प्रकाश गोदारा ने जिला के सभी गाँवों में फसल कटाई प्रयोगों का कार्य कर रहे कृषि विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को आदेश दिए की यह कार्य ध्यानपूर्वक करें क्योंकि इन्ही के आधार पर प्रत्येक गांव की औसत पैदावार तय की जाएगी। उप कृषि निदेशक सुरेंद्र ने बताया कि फसल कटाई प्रयोग के लिए कृषि विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की जिला के सभी गाँवों में ड्यूटी लगाई गई है, जिनके द्वारा प्रत्येक गांव में धान, कपास, बाजरा व मक्का के लिए चार-चार फसल कटाई प्रयोग किए जाने है। आँकड़ों में शुद्धता लाने के उद्देश्य से ही संयुक्त निदेशक द्वारा निरिक्षण का कार्य किया गया ताकि फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर ही जिले की औसत पैदावार निकाली जाएगी। गाँव काहनी में कृषि निरीक्षक सुरेन्द्र का धान व कपास फसल का फसल कटाई प्रयोग, गाँव चुलियाणा में बी.टी.एम. सरेश का धान व बाजरा फसल का फसल कटाई प्रयोग निरिक्षण कृषि विभाग के सयुंक्त निदेशक ओम प्रकाश गोदारा द्वारा किया गया। मौके पर ही फसल की कटाई, झड़ाई का कार्य पूर्ण करवाया गया ताकि आंकड़ो में शुद्धता लाई जा सके। सहायक सांख्यिकी अधिकारी विनोद हुड्डा ने बताया कि हर गाँव से रैंडम नंबर एवं स्मार्ट सैम्पलिंग के आधार पर गाँव में धान, कपास, बाजरा व मक्का फसल के लिए चार-चार खेत चुने जाते है जिसमे 5 बाई 5 के प्लाट का चयन रैंडम तालिका द्वारा किया जाता है। यह कार्य कृषि विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा निदेशालय पंचकुला व उप कृषि निदेशक रोहतक के आदेशानुसार मोबाईल एप के द्वारा पूर्ण करना होता है और औसत पैदावार निकाली जाती है ताकि खंड एवं जिला स्तर की पैदावार निकाली जा सके। इस मौके पर कृषि विभाग, रोहतक से सांख्यिकी सहायक विकास कुमार, नरेंद्र सुपरवाइजर एवं फसल बीमा कम्पनी एआईसी से सुनील भारती, जिला प्रबन्धक और सम्बन्धित गाँव काहनी से किसान कर्मवीर, दलबीर व गाँव चुलियाणा से हवा सिंह आदि मौके पर मौजूद रहें।

दिव्यांगजन भी समाज का अभिन्न अंग होते हैं : एडीसी नरेंद्र कुमार

सुकरमपाल, पब्लिक एशिया

रोहतक » अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार ने हरियाणा दिव्यांग वेलफेयर सोसाइटी के संचालन में अर्पण मानसिक दिव्यांग संस्थान व सरवन व्यस्क सेंटर का दौरा किया। संस्थान में पहुंचने पर स्कूल इंचार्ज नीलम कटारिया ने अतिरिक्त उपायुक्त का स्वागत किया। इस दौरान दिव्यांग छात्र सानिया, ज्योति, अवनी, अंकित, केशव, ईश्वर ने भी एडीसी को स्वागत के तौर पर ग्रीटिंग कार्ड भेंट किए। एडीसी ने निरीक्षण के दौरान संस्था द्वारा दी जा रही सभी प्रकार की सुविधाओं का जायजा लिया और संस्थान संचालकों को जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कक्षाओं में जाकर बच्चों की शिक्षण प्रणाली को देखा। इस दौरान उन्होंने संस्थान में शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों से बात की। एडीसी ने संस्थान के प्रबंधन सदस्यों को

एडीसी नरेंद्र कुमार ने वीरवार को किया अर्पण मानसिक दिव्यांग संस्थान व सरवन व्यस्क सेंटर का दौरा

निर्देश दिए कि दिव्यांग बच्चों को नवीनतम सहायक उपकरणों के माध्यम से शिक्षा एवं अन्य जानकारियां दी जाएं। उन्होंने कहा कि दिव्यांग भी समाज का एक अंग होते है। इन बच्चों को शिक्षित कर समाज की मुख्यधारा में शामिल करना चाहिए। इसके साथ ही हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए कि वे किसी भी दिव्यांगजन के साथ किसी भी तरह का भेदभाव न बरतें। दिव्यांग को एक विशेष तौर पर सहानुभूति और सहयोग की जरूरत होती है। ऐसे में उनको परिवार के साथ-साथ आसपास परिवेश में भी प्यार-प्रेम मिलना जरूरी है।

नगर निगम ने समाधान शिविर लगाकर नगर निगम के संयुक्त आयुक्त भूपेंद्र सिंह ने सुनी नागरिकों की समस्याएं

गुरुवार को आई 12 शिकायतों में से 6 का किया मौके पर ही समाधान

पब्लिक एशिया ब्यूरो

रोहतक » नगर निगम ने वीरवार को अपने कार्यालय में समाधान शिविर का आयोजन किया और नागरिकों की समस्याएं सुनी। इस दौरान अनेक लोग पीआईडी व सफाई व्यवस्था दुरुस्त करवाने, अतिक्रमण हटवाने आदि से संबंधित समस्याएं लेकर पहुंचे। नगर निगम के संयुक्त आयुक्त भूपेंद्र सिंह और अन्य अधिकारियों ने नागरिकों की समस्याओं को सुना और उनका समाधान किया। समाधान शिविर के दौरान संयुक्त आयुक्त भूपेंद्र सिंह ने कहा कि शहरी क्षेत्र के नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए शहरी स्थानीय निकाय द्वारा प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार द्वारा जिला मुख्यालय व उपमंडल स्तर पर शहरी स्थानीय निकाय के कार्यालयों में समाधान शिविरों का आयोजन कर शहरी क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है। नागरिक इन शिविरों में आकर अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं।

वहीं उन्होंने अधिकारियों को नागरिकों को उनकी समस्याओं का तत्परता से समाधान करने के निर्देश दिए। वहीं दूसरी ओर नगर पालिका महम, सांपला और कलानौर में शहरी स्थानीय निकाय के अधिकारियों ने नागरिकों की समस्याएं सुनी। समाधान शिविर में नागरिक अपनी प्रॉपर्टी आईडी, हाउस टैक्स, जन्म प्रमाण पत्र, पानी निकासी आदि

विभिन्न प्रकार की समस्याएं लेकर पहुंचे।अधिकारियों ने नागरिकों की समस्याओं को बड़ी गंभीरता से सुना और उनका समयबद्ध ढंग से समाधान करने का आश्वासन दिया। वीरवार को नगर निगम, रोहतक व नगर पालिका महम/सांपला/कलानौर में कुल 12 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 6 शिकायतों का मौके पर समाधान करवाया गया। अधिकारियों ने कहा कि शेष आवेदनों पर कुछ औपचारिकताएं पूरी होते ही समाधान हो जाएगा। समाधान शिविर में सुभाष नगर निवासी संजीव भांबी गली से अवैध कब्जा हटवाने, आदर्श नगर निवासी केएल शर्मा गली में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करवाने बारे। न्यू जनता कॉलोनी निवासी सतवंती पीआईडी को लिंक करवाने बारे, अजीत कॉलोनी निवासी संतोष देवी पीआईडी ठीक करवाने की शिकायत लेकर पहुंचे। इसी प्रकार अन्य नागरिक भी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए नगर निगम के शिविर में आए।

समाधान शिविर में अधिकारियों ने सभी नागरिकों की समस्याओं को बड़े गौर से सुना। अधिकारियों ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि समाधान शिविर में आने वाले नागरिक समस्या से संबंधित जरूरी दस्तावेज साथ लेकर आएं ताकि एक कार्य के लिए बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने कहा कि नागरिकों की समस्याओं का हर हाल में समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नागरिक प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी टैक्स, सफाई आदि शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित समस्याएं रख सकते हैं, जिनका समाधान प्राथमिकता से किया जाएगा। समाधान शिविर में भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष सतीश चौधरी, मनोनीत पार्षद अमित बंसल, एडवोकेट अंकुश बिड्डू सांसी, एडवोकेट संदीप जांगड़ा के अलावा नगर निगम कार्यालय के संबंधित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

जिला में अब तक 30063.2 मीट्रिक टन धान तथा 6437.60 मीट्रिक टन बाजरा की हुई खरीद : उपायुक्त धीरेंद्र खड़ग़टा

पब्लिक एशिया ब्यूरो

रोहतक » नवनियुक्त उपायुक्त धीरेंद्र खड़ग़टा ने बताया कि जिला की मंडियों में अब तक 30063.2 मीट्रिक टन धान तथा 6437.60 मीट्रिक टन बाजरा की खरीद की गई है। बुधवार को जिला में 1701.5 मीट्रिक टन धान व 70.35 मीट्रिक टन बाजरा की खरीद की गई। धीरेंद्र खड़ग़टा ने बताया कि रोहतक मंडी में 22769.90 मीट्रिक टन ग्रेड-ए किस्म का धान, महम मंडी में 5794 मीट्रिक टन 1509 एवं बासमती 1121 किस्म का धान तथा सांपला मंडी में 1499.30 मीट्रिक टन ग्रेड ए व 1509 किस्म का धान खरीदा गया है। मंडियों से अब तक लगभग 93.25 प्रतिशत धान का उठान किया जा चुका है। कलानौर मंडी में अब तक 2349.35 मीट्रिक टन बाजरा, महम मंडी में 1942.35 मीट्रिक टन बाजरा, रोहतक मंडी में 735.30 मीट्रिक टन बाजरा तथा सांपला मंडी में 1410.60 मीट्रिक टन बाजरा की खरीद की गई है। मंडियों से 87 प्रतिशत बाजरा का उठान किया जा चुका है।

किसान धान के अवशेष न जलाएं »

उपायुक्त : उपायुक्त धीरेंद्र खड़ग़टा ने किसानों का आह्वान किया है कि वे धान की फसल की कटाई के उपरांत फसल अवशेषों को आग न लगाएं। फसल अवशेषों को जलाने से पर्यावरण प्रदूषित होता है तथा पशुओं के लिए चारे की कमी होती है। किसान फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन करें। फसल अवशेषों से पशुओं के लिए चारा भी बनाया जा सकता है तथा किसान कृषि यंत्रों की मदद से फसल अवशेषों की गांठ इत्यादि बनाकर बिक्री कर अतिरिक्त आय भी कमा सकते हैं। फसल अवशेषों को मिट्टी में मिलाकर भूमि की उपजाऊ शक्ति को भी बढ़ाया जा सकता है। फसल अवशेष जलाने वाले किसानों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जा रही है।